RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-04, अंक - 09 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 02 दिसम्बर 2021 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

आप अपनी योग्यता को जानकर और उस पर विश्वास करके एक सुंदर संसार का निर्माण कर सकते है।

दलाई लामा

अक्टूबर से ज्यादा नवंबर में हुआ जीएसटी कलेक्शन

नई दिल्ली। कोरोना काल से रहात मिलेत ही देश की इकोनॉमी एक बार फिर आगे बढ़ चली है। जिसके बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में तेजी देखने को मिली है। बीते महीने नवंबर में अक्टूबर की तुलना में ज्यादा पैसा सरकारी खाते में आया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर महीने में सरकारी खजाने में एक लाख 30 हजार 127 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था।

वित्त मंत्रालय की तरफसे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन एक लाख 31 हजार 526 करोड़ रुपए हुआ है। जो कि अक्टूबर महीने से ज्यादा रहा, क्यों कि नवंबर महीने की शुरुआत में फेस्टिवल सीजन भी रहा। जबकि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा राजस्व कलेक्शन है। सरकारी खजाने में राजस्व की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार के अनुरूप है। इससे पहले इसी वर्ष अप्रैल 2021 में जीएसटी कलेक्शन से 1.41 लाख करोड़ रुपए इक्ट्ठा हुए थे।

भाजपा को राजनीतिक तौर पर इस देश से बाहर देखना चाहती हूं- ममता बेनर्जी

मुम्बई। देश भर में कांग्रेस को झटका देने के आरोपों पर ममता बेनर्जी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि, यदि कांग्रेस पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ सकती है तो फिर टीएमसी गोवा में क्यों नहीं लड़ सकती। त्रिपुरा के निकाय चुनावों में उतरने के बाद ममता बेनर्जी अब गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ममता बेनर्जी ने मुंबई में सिविल सोसायटी की मीटिंग में कहा, मैं भाजपा को राजनीतिक तौर पर इस देश से बाहर देखना चाहती हूं। यदि कांग्रेस बंगाल में लड़ सकती है तो फिर मैं गोवा में क्यों नहीं लड़ सकती? बंगाल की सीएम ने कहा कि, आपको भाजपा के खिलाफ मैदान में रहना होगा और लड़ना होगा वरना वह आपको बाहर फेंक देगी।

ममता बेनर्जी ने भाजपा के खिलाफ सभी क्षेत्रीय दलों से एक होने की अपील करते हुए कहा, 'यदि सभी क्षेत्रीय दल साथ आ जाते हैं तो फिर भाजपा को हराना आसान होगा। मुझे बंगाल से बाहर निकलना होगा। यदि बंगाल में अच्छा काम हो रहा है तो फिर दूसरे राज्यों में क्यों नहीं होना चाहिए।' फिलहाल ममता बनर्जी महाराष्ट्र में हैं, जहां वह आदित्य ठाकरे, संजय राउत के बाद एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात करने वाली हैं। भाजपा की केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने और डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें कम किए जाने को ममता बनर्जी ने चुनावी स्टंट करार दिया।

ममता बेनर्जी ने कहा कि, चुनाव नजदीक आने पर पीएम नरेंद्र मोदी डर गए हैं। इसलिए उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी की है, जबकि इससे पहले लगातार बढ़ रहे थे। इसी तरह उन्होंने कृषि कानूनों को भी वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि, नेताओं की यह आदत होती है कि वे बात ज्यादा करते हैं और काम करते हैं। मेरी नीति अलग है, मुझे बातें करना कम पसंद है और काम करना ज्यादा पसंद है।

बता दें कि, ममता बनर्जी देश भर में नए नेताओं को अपनी पार्टी के साथ जोड़ रही हैं। असम, त्रिपुरा, बिहार, यूपी, गोवा से लेकर हरियाणा तक में टीएमसी ने कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है।

कोविड के दौर में भारत ने मारी 19 वीं स्थान की छलांग

नई दिल्ली। कोविड के दौर में दुनिया में सबसे अच्छे और बुरे रहने के स्थानों की ब्लूमबर्ग की एक रैंकिंग में भारत ने 19 स्थान की छलांग लगाई है। इस वर्ष भारत कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित हुआ, ऐसे में मौजूदा रैंकिंग एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है।

भारत ब्लूमबर्ग की कोविड रेजिलेंस रैंकिंग में अभी 26वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में इस आधार पर फैसला किया गया है कि, कहां कम से कम सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल के साथ सबसे प्रभावी ढंग से वायरस को नियंत्रित किया जा रहा है। रैंकिंग की लिस्ट में वायरस की रोकथाम, अर्थव्यवस्था और फिर से सभी चीजों के खोले जाने आदि 12 बिंदुओं के आधार पर 53 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का आकलन किया है।

तेजी से खुली अर्थव्यवस्था

भारत की रैंकिंग कोरोना की मार के बाद संभलने और तेजी से अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की गति के कारण सुधरी है। शुरू में सुस्त टीकाकरण के बाद इसमें आई तेजी भी एक वजह है। देश ने अभी एक अरब से अधिक टीके की खुराक लोगों को दी जा चुकी है।

भारत की रैंकिंग के सुधार की मुख्य वजहें

भारत की रैंकिंग में बड़ी छलांग के लिए दूसरी बड़ी वजह नवंबर में अपनी उड़ान क्षमता में वृद्धि करना है।

मोदी और देवेगौड़ा की मुलाकात से अटकलें तेज, कांग्रेस को झटका

बेंगलुरु, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के बीच संसद भवन में हुई मुलाकात के बाद कर्नाटक में आगामी विधान परिषद चुनाव के लिये भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के बीच समझौता होने की अटकलें तेज हो गई हैं। भाजपा नेताओं की हुई इस मुलाकात की तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा कीं।

कर्नाटक विधान परिषद के 20 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों की 25 सीटों पर 10 दिसंबर को द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान होगा। इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के चलते चुनाव कराए जा रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता तथा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा चुनाव में उन सीटों पर जेडीएस का खुलेआम समर्थन मांग रहे हैं, जहां वह अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। इस पृष्ठभूमि में मोदी-देवेगौड़ा की मुलाकात का घटनाक्रम सामने आया है।

जेडीएस ने केवल छह सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा और कांग्रेस 20-20 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय राजधानी मे गौड़ा ने कहा था कि, इस मामले पर चर्चा हुई और भाजपा को इस संबंध में अंतिम फैसला करना है जबकि जेडीएस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री एचडी. कुमारस्वामी निर्णय लेंगे।

देवगौड़ा ने कहा, इस मामले पर फैसला लेना अंततः भाजपा पर निर्भर करता है, क्योंकि वह सत्ता में है। कुमारस्वामी ने इस (प्रस्ताव) पर नकारात्मक बात नहीं की है। अंतिम निर्णय भाजपा पर निर्भर करता है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि यह आप लोगों पर निर्भर है कि आप फैसला लें।

ओमिक्रॉनः नहीं शुरू होंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट का असर भारत में पूर्व निर्धारित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर पड़ा है। पहले सरकार की तरफसे बताया गया था कि, एक फैसले में तय किया गया है कि 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किया जाएगा। लेकिन अब इस फैसले को टाल दिया गया है। यानी अब भारत में 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नहीं हो पाएंगी।

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफसिविल एविएशन की तरफसे कहा गया है कि, वो अपने पूर्व के फैसले की समीक्षा करेगा।

दक्षिण अफ्रीकी देशों में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत और ब्रिटेन-बेल्जियम समेत कई देशों में यह वायरस पहुंच जाने के बाद भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। डीजीसीए ने कहा कि, वह कोरोना वायरस के नए वैरिएंट के उभार को देखते हुए स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। डीजीसीए ने कहा कि वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री एयरलाइन सेवाओं को फिर से शुरू करने की तारीख पर अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इसमें 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा गया था। पीएम ने विदेश से आने वाले लोगों की सख्त निगरानी करने की बात भी कही थी। इसी बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन वैरिएंट ने तांडव मचा दिया है। कई देशों में इस खतरनाक वैरिएंट को लेकर गाइडलाइंस बना दी गई हैं, वहीं कई जगह इसे लेकर ऐहैतियात बरती जा रही है। वैरिएंट को डब्लूएचओ ने पहले ही 'वैरिएंट ऑफ कंसर्न', यानि चिंताजनक घोषित किया है।

अभी कुछ भी नहीं होगा बंद लेकिन कोरोना से रहे सावधान

भोपाल। शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन और मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर-जबलपुर में सामने आ रहे पॉजिटिव केसों पर चिंता जताई है। एमपी की डिस्ट्रिक, ब्लॉक और पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि, अभी कुछ भी बंद नहीं होगा, लेकिन कोरोना से सावधान रहें, वरना हालात मुश्किल भरे हो जाएंगे। आज सावधानी नहीं रखी तो परिस्थितियां बहुत विकट वाली हो जाएंगी, हम नहीं चाहते कि, फिर से लॉकडाउन लगे। मध्यप्रदेश में 24 घंटे में 17 केस आए हैं, जिसमें भोपाल में फिर नए 9 केस, इंदौर में 5, जबलपुर में 2 और अशोकनगर में 1 पॉजिटिव शामिल हैं। मीटिंग में मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर के साथ डिस्ट्रिक, ब्लॉक और पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य वर्चुअल मिटिग से जुड़े।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नोटिस जारी करेगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को नोटिस जारी करेगी। नोटिस प्रतिबंध के बावजूद सेंट्रल विस्टा में निर्माण कार्य कराए जाने और धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने के लिए भेजी जाएगी।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। राय ने कहा, ''निर्माण एवं ध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद हमें सेंट्रल विस्टा परियोजना स्थल पर काम कराए जाने के बारे में कई फोन आ रहे हैं। जांच के दौरान हमने पाया कि यह सही है।''

उन्होंने कहा, ''हम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से कहेंगे कि सीपीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी कर वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कराए जाने के कारणों के बारे में पूछें।''

राय ने कहा कि, निर्माण स्थल पर धूल प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के लिए एजेंसी को अलग से नोटिस जारी किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पहले कहा था कि, वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए राजधानी में अगले आदेश तक निर्माण एवं ध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

शराबी पुत्र ने जन्म देने वाली मां का गला घोट मौत के घाट उतारा

मामलाः रोज पत्नी के साथ करता था विवाद मां ने बहू को घर से भाग जाने को कहा तो घटना को दिया अंजाम

बालाघाट। मध्यप्रदेश के बालाघाट में एक युवक ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। महिला, पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में बीच-बचाव करने आई थी। इसके बाद बेटे ने पहले मां का गला घोंटा, इसके बाद शव को घसीटकर कुएं में फेंक दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात परसवाड़ा थाना क्षेत्र के कटंगा गांव में हुई।

गांव में सुखदेव वरकड़े अपनी मां और पत्नी के साथ रहता है। सुखदेव शराब का आदी है। नशे में धुत होकर आए दिन वह मां और पत्नी के साथ मारपीट करता है। मंगलवार रात भी नशे में धुत होकर घर आया और किसी बात पर पत्नी लताबाई से झगड़ा शुरू कर दिया तथा पत्नी के साथ मारपीट की, इस बीच सुखदेव की मां धनवंता बाई वरकड़े (58) बहू को घर से भाग जाने के लिए कह दिया। इस पर सुखदेव ने धनवंता बाई वरकड़े का गमछे से गला घोंट दिया। धनवंता बाई की मौके पर ही मौत हो गई।

यही नहीं, वारदात के बाद उसने मां के शव को घसीटकर सूखे कुएं में फेंक दिया। इसके बाद घर में रातभर सोता रहा। सुबह लोगों ने धनवंता बाई के शव को देखा इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी।

आए दिन झगड़ा करता था आरोपी

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की तफ्तीश को लेकर एफएसएल टीम भी पहुची आरोपी की पत्नी लता बाई ने बताया कि, पति मेरे साथ रोज लकड़ी, पत्थर से मारपीट और झगड़ा करता है। मंगलवार रात भी मारपीट की। सास ने मुझे घर से भाग जाने को कहा मैं रात 2 बजे घर से पहचान वाले घर चली गई सुबह पता चला कि पति ने सास को मार डाला है।

पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुथी, धोलावाड़ के जंगल में युवक की मिली थी लाश

अवैध संबधों को लेकर गुप्तांग पर वार कर व गला काटकर की थी हत्या

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के रावटी थाना क्षेत्र अंतर्गत धोलावड़ के जंगल में युवक की हत्या कर उसकी लाश फेंकने के मामले में पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। वही हत्या के पीछे की वजह अवैध संबध की बात भी सामने आई है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को नवीन कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि, रावटी थाना क्षेत्र अंतर्गत धोलावड़ रोड के किनारे जगल में एक युवक की लाश मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची रावटी पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की तो जांच के दौरान मृतक की पहचान वालचन्द्र पिता भीलजी डोडियार 26 वर्षीय निवासी पाड.लया जोतपुरा थाना बाजना के रूप हुई। जांच के दौरान पुलिस को मृतक के अवैध संबध की जानकारी मिली। थाना बाजना अपनी प्रेमिका से बातचीत होने उससे मिलने के लिए ग्राम भूरीघाटी गया था। जहा रात्रि में 8 बजे करीब अपनी प्रेमिका से मिलने पर प्रेमिका के पति राजेश पिता बेहरिंग मैड़ा द्वारा वालचंद और उसकी पत्नी को मिलते हुए देख लिया था। जिससे राकेश काफी आक्रोशित हो गया और उसने वालचंद के गुप्तांग पर दराते से हमला कर दिया। घायल अवस्था में वालचंद गेहूं के खेत की तरफ भागने लगा जिसका पीछा कर रहे हैं राजेश ने वालचंद को पकड़ लिया और दराते से उसका गला काट दिया। वालचंद की हत्या होने के बाद आरोपी राजेश ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने ही गांव के निवासी विकास पिता रसिया की मदद ली। दोनों आरोपियों ने मिलकर मृतक की लाश के सर की ओर प्लास्टिक की थेली बांध कर मृतक को उसी की मोटर सायकल के साथ धोलावाड़ डेम के पास फेक दिया। आरोपियों ने अपने गांव पहुंचने के लिए वही गांव के एक नाबालिक बालक को मोटरसाइकिल से रावटी लेने को बुलाया और आरोपियों ने मृतक का मोबाइल बालक को तोड़ कर फेकने के लिए दे दिया। पुलिस ने मामले में बालक को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने वॉलचंद की हत्या में आरोपी राजेश मैड़ा, विकास मैड़ा और अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया है।

कश्मीर में हमले घटे और घुसपैठ में आई गिरावट

नई दिल्ली, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का असर दिखने लगा है और अब न सिर्फ आतंकी हमलों में गिरावट आई है बल्कि घुसपैठ के मामले भी घटे हैं। सरकार ने बुधवार को संसद में इसकी जानकारी दी है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया है कि इस साल अब तक घुसपैठ के सिर्फ28 ही मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि बीते सालों की तुलना में काफी कम हैं।

गृह मंत्रालय के जवाब के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में साल 2018 में घुसपैठ के कुल 143 मामले दर्ज किए थे, जबकि इस साल नवंबर महीने तक यह आंकड़ा सिर्फ28 तक सिमटा हुआ है।

वहीं, गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि, वर्ष 2018 में घाटी में आतंकवाद से जुड़े कुल 417 मामले आए थे। इस साल नवंबर माह तक के आंकड़ों को देखें तो यह संख्या 244 है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि कश्मीर में रहने वाले 115 कश्मीरी पंडितों के परिवार अक्टूबर 2021 में जम्मू जाकर बस गए हैं। हालांकि, इनमें से अधिकांश परिवार सरकारी कर्मचारियों के हैं, जिनमें से कुछ सर्दी की छुट्टियों के कारण जम्मू गए हैं।

फ्लॉप शोः प्रशासन ने नहीं की भीड़ की व्यवस्था गौरव यात्रा में भाजपा भी नहीं जुटा सकी भीड़

गौरव यात्रा फ्लॉप शो लाखों के खर्च के बाद भी नहीं जुटा पाए भीड़, खाली कुर्सियों के सामने भाषण देते रहे नेता

प्रदेशाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के क्षेत्र में नहीं आये लोग, लगी फटकार, देश के सबसे बड़े संगठन की हालत खराब

मेघनगर में खाली कुर्सियों को भाषण देते प्रभारी मंत्री और नेता।

मंच पर बैठे नेता के साथ खाली कुर्सियों को गौरव यात्रा का मानस बताते जिलाध्यक्ष।

बामनिया में गिनती के लोगो को संबोधित करते अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष।

पेटलावद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को बुला कर भीड़ बढ़ाने की प्रशासन की कोशिश हुई नाकाम, नही जुटे लोग।

माही की गूंज ,झाबुआ

देश का सबसे बड़ा संगठन भाजपा के पास 14 से अधिक प्रकोष्ठ और 7 मोर्चे है अगर हर मोर्चे के सब पदाधिकारी भी एक जगह जमा हो जाए तो सैकड़ो कार्यकर्ताओ की भीड़ बिना किसी व्यवस्था के जमा हो जाए, लेकिन देश के इस बड़े संगठन की हवा झाबुआ जिले में एक झटके में निकल गई। जनजाति मोर्चे के नेतृत्व में निकलने वाली गौरव यात्रा जो रतलाम से निकल कर पाताल पानी जाने वाली है, उसका झाबुआ जिले का हिस्सा भाजपा के लिए किसी काले दिन से कम नही माना जाएगा। सबसे बड़ी बात अजजा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाबर के ग्रह जिले में यात्रा की ऐसी दुर्गति की उम्मीद प्रदेश संगठन ने तो कम से कम नही लगाई होगी। वही विवादित जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक को भी आज जमीन दिख गई जो रोज सैकड़ो कांग्रेसीयो को भाजपा में शामिल करने का दावा करते रहते हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी छोड़ कर आने वाले कांग्रेसी तो ठीक उनके जिला संगठन और मंडल क्षेत्र के पदाधिकारी भी यात्रा में नही पहुँचे, जिसके बाद अब उनके संगठन पर नियंत्रण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी यात्रा की व्यवस्था प्रशासनिक थी लेकिन भीड़ जुटाने को लेकर भाजपा और प्रशासन में असमंजस की स्थिति बनी रही। भाजपा मुगालदे में थी कि, उनके कार्यकर्ताओ की भीड़ भी आ गई तो संख्या अच्छी हो जाएगी और कई स्थानों पर मंच ऐसे स्थान पर बनाये गए जहा कम भीड़ को भी अधिक बताया जा सके। लेकिन ये योजना भी भाजपा की फैल हो गई, उम्मीद से भी बहुत कम जुटी भीड़ ने भाजपा संगठन की पोल खोल कर रख दी।

माही से लेकर राणापुर तक फ्लॉप रहा आयोजन, कही भी नही पहुँचे समय पर

मंगलवार को सुबह 8 बजे यात्रा का प्रवेश रतलाम जिले से झाबुआ जिले मे होना था। सुबह 10 बजे बामनिया में पहुँच कर सभा से लेकर राणापुर से आलीराजपुर जिले में यात्रा के पहुँचने का पूरा समय निर्धारित था, हर मंडल क्षेत्र में 200 से 300 दुपहिया वाहनों की रैली का लक्ष्य था, लेकिन न ही यात्रा कही समय पर पहुँची और न ही भाजपा के कार्यकर्ता और आदिवासी वर्ग जुटपाया। दुपहिया वाहनों के नाम पर बमुश्किल 25 से 30 दुपहिया वाहनों के साथ 10 बजे की जगह 1 बजे बामनिया पहुँची जहा बमुश्किल 100 से 150 लोगो की सभा के साथ काफिला पेटलावद पहुँचा ओर भीड़ नही होने से प्रसाशन ने ताबड़तोड़ पेटलावद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बुला कर मंत्रीजी के सामने भीड़ जमा करने की कोशिश की, जो पूरी तरह से सफल नही हो सकी। यात्रा पेटलावद से अपने अगले पड़ाव के लिए निकल गई जहा स्थिति और दयनीय हो गई।

मेघनगर में खाली कुर्सियों को भाषण दे गए प्रभारी मंत्री व प्रदेशाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, महामंत्री के गृह क्षेत्र में हालत हुई खराब

शिवराज सरकार की गौरव यात्रा पर उस वक्त पानी फिर गया जब गौरव यात्रा मेघनगर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां अलग ही नजारा देखने को मिला। मंत्रीजी ने खाली पड़ी कुर्सियों को देख दांतो तले उंगली दबा दी, जहां सुनने वाले कम और मंच पर भाषण सुनाने वाले ज्यादा दिखाई दे रहे थे। मंच पर जिले के प्रभारी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कलसिह भाभर, भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण नायक, जिला महामंत्री गौरव खंडेलवाल, सोम सिंह सोलंकी, जिला मंत्री भुपेश भानपुरिया सहित मेघनगर, मदरानी, काकनवानी मंडल के मंडल अध्यक्ष ओर भूतपूर्व नेता की फ़ौज मौजूद थी, तो ठीक सामने की ओर एका-दुक्का श्रोताओं के अलावा खाली पड़ी सुनने वाली कुर्सियो का यहां का नज़ारा देखने वाला था। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के भाषण के दौरान एक अजब नजारा देखने को मिला लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी प्रशासन व भाजपा के नेता भीड़ नहीं जुटा सका। मंच पर बैठे मंत्री सहित सारे नेता खाली पड़ी कुर्सियों को भाषण सुनाते रहे, बताया जा रहा हैं कि, प्रभारी मंत्री ने भाजपा के स्थानीय नेताओं को कड़ी फटकार भी लगाई, मंच पर बैठे नेता अपने ग्रह क्षेत्र में ही भीड़ नही जुटा पाए जिसकी किरकिरी मंत्री जी सहित सोशल मिडिया पर साफदेखी जा सकती है। वही दूसरी ओर मेघनगर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री मिडिया में सिर्फमंच के एक ओर की तस्वीरों को वायरल कर अपनी छाती 56 इंच की बता रहे, जबकी मंच की दुसरी ओर खाली पड़ी कुर्सियों ने हवा छाप नेताओ की वास्तविकता बया कर हवा निकाल दी।

दिनभर परेशान होते रहे प्रशासनिक कर्मचारी, फोटो छाप नेताओं की हकीकत सामने आई

मेघनगर मे गौरव यात्रा के स्वागत की सूचना दोपहर 12 बजे दी गई थी, जो यात्रा देर शाम 6 बजे मेघनगर पहुँची। ऐसे में नगर परिषद महिला बाल विकास एवं अन्य विभाग की महिलाएं स्वागत कलश को कभी इधर तो कभी उधर रख इंतजार कर दिनभर भूख-प्यास से परेशान रही। सोशल मिडिया के फोटो छाप नेता पूरे कार्यक्रम के दौरान बगले झांकते रहे और मंत्री के साथ सेल्फी तक लेने की हिम्मत नही जुटा सके। जिस स्कूल में सभा का आयोजन था वहां बच्चों की परीक्षा भी हो रही थी और दिन भर माइक भी चलता रहा, आयोजन में प्रशासन की और से जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, वो यात्रा के इंतज़ार मे परेशान होते रहे। दिन में 2 बजे झाबुआ पहुँचने वाली यात्रा रात की 9 बजे पहुँची जहा से बुधवार को आलीराजपुर जिले के लिए रवाना हुई।

बामनिया में प्रभारी मंत्री के पास की कुर्सी खाली छोड़ कर उसे सेल्फी पॉइंट बनाया गया, नेता पास बैठ-बैठ कर सेल्फी खिंचवाते रहे।

क्या होगी प्रशासनिक सर्जरी, समय से नहीं संभाली प्रशासन ने व्यवस्था, रतलाम जिले में जुटी अच्छी भीड़

यात्रा का पूरा आयोजन तय था, जिसकी तैयारी के लिए प्रशासन के पास पूरा समय था, जहां एक ओर रतलाम कलेक्टर यात्रा को लेकर लगातार प्रशासन के साथ बैठक कर यात्रा को सफल बनाने में जुटे थे। वही झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा और पेटलावद एसडीएम शिशिर गेमावत यात्रा को लेकर कोई तैयारी नही करते देखे गए और यात्रा से दो दिन पूर्व रविवार को मैदान में उतरे, जिससे आयोजन का पूरा माहौल फैल हो गया। सबसे बड़ी बात आयोजन को लेकर कोई प्रचार-प्रसार तक नही किया गया, मीडिया को भी भाजपा और प्रशासन की और से यात्रा की कोई जानकारी नही दी गई। भाजपा नेता और प्रशासनिक अधिकारी भीड़ जुटाने को लेकर एक-दूसरे पर बिल फाड़ रहे हैं। अब भाजपा संगठन अपनी टांग ऊपर रखने के चक्कर मे प्रशासनिक सर्जरी भी कर सकते हैं। राजस्व मामले सहित स्थानीय स्तर पर पूरी तरह से फेल हो चुके जिला कलेक्टर सहित आईएस एसडीएम शिशिर गेमावत सहित आयोजन में लगे कई अधिकारी को इधर-उधर किये जाने की चर्चा प्रशासनिक गलियारों में शुरू हो चुकी हैं।

कलेक्टर के बंगले में हो गया डामरीकरण, नगर की सड़के हो रही खस्ताहाल

माही की गूंज, झाबुआ। वो कहते है ना कि ''अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता'' कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों जिला मुख्यालय पर देखने को मिल रहा है। नगर की सड़कें इन दिनों सभी जगह से खस्ताहाल नजर आ रही है। शहर का नेहरू मार्ग हो, कैलाश मार्ग हो, शहर के गुजरने वाला कुक्षी-फुलमाल मार्ग हो या फिर शहर के बीच से गुजर रही उत्कृष्ट सड़क। सभी मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे है। उत्कृष्ट सड़क के हाल तो इतने खराब है कि, यह पूरी तरह से अब गड्ढों में तब्दील होती नजर आ रही है। मंडी के मुख्य द्वार से लगाकर पोलेटेक्नीक कॉलेज के मुख्य द्वार तक यह मार्ग गड्ढों से पटा पड़ा है। कलेक्टर निवास तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सीमप से लगाकर पुलिस अधीक्षक के बंगले तक इसकी हालत खस्ता है। जेल बगीचे के समीप बनी पुलिया पर तो सड़क की उपरी परत मानों गायब सी हो गई है। इसके अलावा मेघनगर नाके पर भी इस सड़क पर गड्ढे हो चुके है। मेघनगर नाके पर जब से उत्कृष्ट सड़क बनी है, उसके कुछ दिनों बाद से ही यह समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण घरों व होटलों का गंदा पानी इस सड़क पर 12 महीनों बहता ही रहता है। कुल मिलाकर शहर की उत्कृष्ट सड़क लगातार बदहाली की ओर बढ़ती जा रही है। हालांकि नगरपालिका ने नगर की सड़कें सुधारने को लेकर पहल तो की है, लेकिन यह पहल कब तक पूर्ण होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। चूंकि डेढ़ -दो साल में फिर से नगरपालिका चुनाव होना है तो चुनाव के मद्देनजर वर्तमान परिषद ने इस ओर कदम उठाए है, वरना पिछले सालों में तो शहर की सड़कों के हालात बदतर ही रहे है। हालांकि शहर के कुछ वार्डों में नगरपालिका द्वारा डामरीकरण किया गया है, मगर शहर की मुख्य सड़कों से अब तक दूरी बनाए रखी है। उत्कृष्ट सड़क की बदहाली को देखते हुए नगरपालिका ने पिछले दिनों अधिकारियों के बंगलों के सामने जरूर कुछ पेंचवर्क का कार्य किया था। मगर वह भी अब नाकाफी साबित हो रहा है।

इसके विपरीत जिले के आला अधिकारियों के बंगलों में अनावश्यक ही डामरीकरण के कार्य किए जा रहे है। खुद जिला कलेक्टर के बंगले में अभी हालही में डामरी करण का कार्य किया गया। जबकि कलेक्टर के बंगलें में किसी तरह का कोई भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकता। सिर्फकलेक्टर का वाहन ही बंगले के अंदर जाता है। बावजूद इसके बंगले के अंदर मार्ग पर डामरीकरण कहां तक उचित है...? जबकि जनता, कलेक्टर कार्यालय व बंगले के सामने से गुजर रही बदहाल उत्कृष्ट सड़क पर सफर करने को मजबूर है। इसी उत्कृष्ट सड़क पर जिले के तमाम आला अधिकारियों के बंगले है, मगर इन अधिकारियों को बंगलों के बाहर से गुजर रही इस खस्ताहाल उत्कृष्ट सड़क से कोई लेना-देना नहीं है। हालात और स्थिति को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ''जनता के सेवकों को जनता का ध्यान नहीं है।''

वैसे भी जिला मुख्यालय अब हर क्षेत्र में बद से बदतर स्थिति को पहुंचता जा रहा है। नगर के सौंदर्यीकरण के कार्य हो या बदहाल सड़कें सभी जगह हालात दिनहीन ही नजर आ रहे है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भी शहर फिसड्डी ही साबित हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रैटिंग में लगातार गिरावट इस बात की गवाह है कि यहां सबकुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। शहर के तालाब लगातार शहर में गंदगी व बदबू का पर्याय बनते नजर आ रहे है और जिले के आला अधिकारी स्वच्छता के नाम पर लगातार ढकोसला करते हुए फोटो शेशन करवाने में मस्त है। अच्छा होगा अगर जिले के आला अधिकारी नगर की जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को उन तक पहुंचाने का ईमानदारी से प्रयास करे। वरना जो है, सो तो है ही। जनता को भी इसकी आदत है। आप नही करेंगे तो आपके बाद आने वाला कोई ओर अधिकारी करेगा। मगर यह कहनी रह जाएगी कि पिछले अधिकारियों ने शहर का सत्यानाश ही किया है। वैसे भी यह गरीब आदिवासी बाहुल जिला अधिकारियों के लिए प्रयोग शाला तो रहा ही है।

सुने घरों के बाद चोरों ने बनाया दुपहियां वाहनों को निशाना

गार्डन, पार्किंग, होटल के बाहार और न्यायलय परिसर से दिन दहाड़े चोरी की गाड़ी

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद क्षेत्र में सुने घरों को निशाना बना कर चोरी करने के लगातार मामले आने के बाद वाहन चोर गिरोह ने पुलिस की नींद उड़ा दी। ये चोर गिरोह रात में नही लोगों के जागते उनकी आँखों के सामने से वाहन उड़ा कर ले जा रहे है। बड़ी बात ये की चोरो ने न्यायलय परिसर तक को भी नही छोड़ा। बीते 5 दिन में वाहन चोरी की घटना पेटलावद थाना क्षेत्र में 4 वारदात सामने आ चुकी जो कि, हमारी जानकारी में जबकि और भी मामले ऐसे होने की जानकारी मिल रही जिसकी पुष्टि पुलिस इसलिए नही कर रही है, क्योंकि मामले दर्ज नही हुए है जो जानकारी हमको मिली वो सीधे वाहन मालिक से मिली है जबकि वाहन चोरी की घटना हमारी जानकारी से भी अधिक हुई है।

गार्डन, पार्किंग, होटल के बाहर और न्यायलय परिसर से दिन दहाडे चोरी हुई गाड़ी

बीते 5 दिनों में चोरो ने थाना पेटलावद क्षेत्र से तीन, जबकि चौकी बामनिया क्षेत्र से एक वाहन चोरी की वारदात होने की जानकारी मिली है। 27 नवम्बर को थांदला रोड स्थित प्रेम सागर से ओम प्रकाश नागर का दुपहिया वाहन क्रमांक एमपी 45 एमके 8669, न्यायालय परिसर से 27 नवम्बर को धुलसिह डिंडोर का पार्किंग में खड़ा वाहन क्रमांक एमपी 45 एमएच 1430 और एक दुपहिया वाहन न्यू चॉइस होटल के बहार से मानसिंह देवड़ा की गाडी चोरी हो गई। इसी प्रकार बामनिया रेलवे स्टेशन के बाहार से भी एक वाहन चोरी होने की जानकारी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व भी न्यायलय परिसर से एक वाहन चोरी होने की जानकारी मिल रही है, पुलिस को चुनोती देते हुए वाहन चोर रात के अंधेरे में ही नही दिन के उजाले में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं।

एसडीओपी सोनु डावर ने इस संबंध में बताया कि, चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस हर प्रकार से लगी हुई है जल्द है चोरो तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है।

कांग्रेस ने निकाली जनजागरण यात्रा

माही की गूंज, थांदला। विधानसभा क्षेत्र में 19 से 30 नवम्बर तक ग्रामीण क्षेत्रो में प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी ओर भ्रष्टाचार को ले कर जनजागरण यात्रा निकाली गई। मंगलवार को ब्लाक कांग्रेस के बैनर तले जनजागरण यात्रा नगर में निकाली गई। यात्रा का शुभारम्भ पुरानी मंडी प्रांगण से हुआ, जो कुम्हार मोहल्ला, पिपली चोराहा, आजाद चोक, सिविल अस्पताल होता हुआ ईमली गणेश मंदिर चोराहा पहुचा। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों के बैनर झंडे हाथ मे लिए चल रहे थे। रैली के समापन अवसर पर नुक्कड़ सभा हुई जिसे विधायक विरसिह भूरिया युवा नेता जसवंत भाभर, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष गेंदालाल डामोर आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर रैली में किसान कांग्रेस के नंदलाल मेण, राजेश जैन काऊ, मसुल भूरिया, रालु वसुनिया, हरीश पंचाल सहित सेकड़ो कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल थे।

डेढ़ घंटे के श्रमदान की नौटंकी में ही लूट लोगे क्या वाहवाही?

अगर ऐसे श्रमदान से कुछ होता तो, जिला कब का स्वर्ग बन चुका होता

माही की गूंज, झाबुआ।

बहादुर सागर तालाब में फैल रही गंदगी व जलकुम्भी को लेकर अखबरों में समाचार प्रकाशन के बाद कुम्भकर्णी नींद से जागे प्रशासनिक अमले व नगरपालिका ने ताबड़तोड़ तालाब से जलकुम्भी निकालने का काम शुरू किया। नगरपालिका ने अपने स्तर पर काम शुरू तो किया मगर यह इतना भी आसान नहीं था। नगरपालिका के काम शुरू करते ही 16 नवंबर को कलेक्टर सोमेश मिश्रा अचानक तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे। पहले दौरे में कलेक्टर साहब ने साफ-सफाई व स्वच्छ जल हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही तालाब में गम्बुजिया मछली डालने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर मिश्रा ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा था कि, इतनी बड़ी मात्रा में जलकुंभी हटाना एक बड़ा काम है इसे हम सभी जनसहयोग से हटाना चाहते है। इसके लिए एक समय का निर्धारण तत्काल किया जाए। इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए तत्काल लाइट, बैंच, जाली, फव्वारा लगाए जाए। इसके अतिरिक्त जो जलकुंभी निकाली जाएगी उसे ट्रेंचिंग ग्राउंड पर एकत्र कर उसकी खाद्य निर्मित की जाए। सौंदर्यीकरण के लिए एक डीपीआर तत्काल बनाकर प्रस्तुत की जाए।

कलेक्टर के कहे अनुसार जनसहयोग से इस कार्य के लिए एक समय का निर्धारण करना था। मगर 16 नवंबर के बाद समय बीतता गया मगर किसी तरह का कोई जनसहयोग अबतक बहादुर सागर तालाब के स्वच्छता अभियान को नहीं मिला। तालाब से जलकुंभी निकालने के लिए नगरपालिका स्वच्छता शाखा की टीम लगातार अकेले ही संघर्ष करती रही। एक हफ्ते नगरपालिका की टीम ने लगातार काम करते काफी जलकुंभी तालाब से निकाल भी दी। मगर जैसा कि कलेक्टर साहब ने कहा था यह एक बड़ा काम है तो नगरपालिका की टीम की गति के हिसाब से इसे साफ करने में महीनों लग जाएंगे। इस बीच न कलेक्टर साहब तालाब पर दौबारा पहुंचे और न ही उनका जनसहयोग। इसको लेकर माही की गूंज ने अपने पिछले अंक में ÷ऐसे तो नहीं होगा बड़ा तालाब जलकुंभी से मुक्त, कलेक्टर व उनका जनसहयोग अब तक नहीं पहुंच सका तालाब सफाई के लिए÷ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। समाचार प्रकाशन के दिन ही यानि 10 दिन बाद 25 नवम्बर को कलेक्टर दौबारा तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे। मगर न तो उन्होने और न ही उनके साथ पहुंचे अमले ने इस कार्य में किसी तरह का कोई जनसहयोग किया।

हां इतना जरूर हुआ कि, साहब की सरकारी प्रेस यानि जनसंपर्क विभाग ने 17 नवंबर को जारी प्रेसनोट की हुबहु कॉपी करते हुए 25 नवंबर का बनाकर जारी कर दिया। इस जारी प्रेसनोट में तब्दीली सिर्फइतनी सी थी कि, साहब ने यहां एक जेसीबी मशीन और लगाने के निर्देश दिए इसके अलावा उन्होने जनसहयोग के लिए अगली तारीख की घोषणा करते हुए 28 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी सामाजिक संगठनों से सहयोग लेकर तालाब स्वच्छ बनाने की अपील की। जिसके बाद कलेक्टर साहब अपने अमले के साथ यहां से रवाना हो गए।

बारी जब 28 नवंबर को जनसहयोग की आई, तो सुबह कलेक्टर साहब अपने लवाजमें के साथ बड़े तालाब स्थित छतरी घांट पर पहुंचे। चूंकि 28 नवंबर को साहब के जनसहयोग की घोषणा पहले ही हो चुकी थी तो साहब के अधिनस्त व फोटो खिंचाउ संस्थाओं के लोग भी यहां साहब के पहले ही पहुंच गए थे। कलेक्टर दिए गए समय के अनुसार सुबह 9 बजे तालाब पहुचे और सफाई का यह जनसहयोग अभियान शुरू हुआ। जब यह अभियान शुरू हुआ तो लग रहा था कि जैसे दिन चढ़ेगा वैसे -वैसे जनसहयोग भी बढ़ेगा। क्योंकि यह अभियान शाम 5 बजे तक चलना था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि करीब एक से डेढ़ घंटे में ही इस जनसहयोग अभियान ने दम तोड़ दिया। करीब डेढ़ घंटे में ही कलेक्टर साहब इस अभियान को अधर में छोड़कर रवाना हो गए और उनके जाते ही उनके अधिनस्तों और सामाजिक संस्थाओं के फोटो खिंचाउ सदस्यों की भी हवा निकल गई और वे भी फोटो सेशन के बाद घर की ओर रवाना हो गए। मात्र डेढ़ घंटे के हो-हल्ले के बाद कोई तालाब पर काम करता नजर आया तो वह था नगरपालिका की स्वच्छता शाखा की टीम।

अब सवाल यह उठता है कि, क्या साहब श्रमदान के नाम पर मात्र वाहवाही लूटने व फोटो खिंचवाने के लिए ही आए थे...? अगर ऐसा है तो फिर यह जिले के लिए एक बड़ी विडम्बना की बात है कि, जिले का एक शीर्ष अधिकारी सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए फोटो खिंचाउ अभियानों के आयोजन करता है। अगर वाकई यह कलेक्टर साहब की हार्दिक इच्छा है कि, बहादुर सागर तालाब का सौंदर्य वापस लौट जाए तो यकीन मानिए इस तरह के अभियानाओं से कुछ होने वाला नहीं है। अगर इस तरह के अभियानों से कुछ हो पाता तो यह जिला कब का स्वर्ग बन गया होता।

अब आगे की साहब की रणनीति क्या होगी यह तो समय ही बताएगा। अगला जनसहयोग अभियान कब और कैसे होगा, कितना जनसहयोग अगली बार मिलने वाला है, साहब अपने बोल वचनों पर कितने खरे उतरेंगे। यह सारी बातें अभी तो समय के गर्त में ही है... फिर आगे तो भगवान ही मालिक है...।

कई विभागों की भूमि पर भी माफियाओं की नजर, अतिक्रमण को लेकर विभागों की भूमिका संदिग्ध

कौड़ियों की भूमि को दलालों ने कर दी करोड़ों की, शासकीय भूमि की आड़ में चल रहा कृषि भूमि बेचने का खेल

भोपाल से आई जांच को भी जिला और स्थानीय प्रशासन ने हवा में उड़ाया

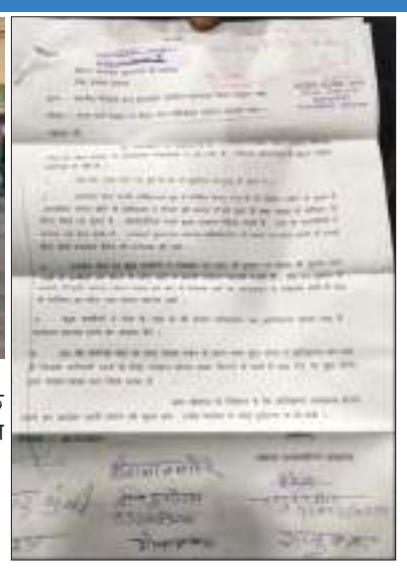

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद विकास खण्ड में जमीन खोर बिच्छु सरकारी और शासन द्वारा विभागों को आवंटित भूमि को धीरे-धीरे कुरेत कर लोगो की सरकारी भूमि से लगी जमीनों से जोड़ कर जमीन की कीमतों को करोड़ो में ले गए और जमीन की दलाली में अपने व्यारे-न्यारे कर लिए। पेटलावद से हो कर गुजर रहे थांदला-बदनावर स्टेट हाइवे पर सड़क से दूर स्थित कृषि भूमि की खरीद फरोख्त का कार्य अभी जोरो पर चल रहा है, खासकर पेटलावद से लेकर करडावद, मोहनपुरा और कसारबड़ी तक स्थित सामान्य वर्ग की कृषि भूमि की कीमत सरकारी गाइड लाइन से दो-चार नही बल्कि सैकड़ो गुना अधिक कीमत में बिक रही है, जमीन खोर दलालों की इस क्षेत्र पर ऐसी माया हुई कि कौड़ियों के दाम नही बिक रही जमीनों की कीमत आज करोड़ो में है।

करड़ावद से हुई शिकायत के बाद सामने आया मामला, सड़क और निजी कृषि भूमि के बीच स्थित हैं शासकीय भूमि

ग्राम पंचायत करड़ावद के कुछ युवाओं ने स्टेट हाइवे से लगी भूमि पर दबंगो ओर भूमाफिया के कब्जे होने की शिकायत की जिसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ, स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने और कोई कार्रवाई करने में कोई रुचि नही दिखाई, शिकायतकर्ताओं ने जब भूमि का पुराना रिकॉर्ड राजस्व शाखा से निकाला तो पता चला कि, न केवल करोड़ों की बेशकीमती शासकीय भूमि पर लोगों का कब्ज़ा है, जबकि शासन द्वारा कई विभागों को आवंटित भूमि पर भी दबंगो ने कब्जा जमाया हुआ है। स्थानीय प्रशासन भी पूरे मामले से अनभिग्य नही है शिकायत के बाद प्रशासन ने शासकीय भूमि को नपती कर मुक्त करने के बज़ाये लेन-देन का बड़ा खेल शुरू कर दिया और अतिक्रमण के मामले राजस्व दर्ज कर तारीखों के नाम पर मामले उलझाए जा रहे हैं। स्टेट हाइवे पर पेटलावद से लेकर करडावद और उससे भी आगे तक रोड के पास कृषि भूमि है, सड़क और कृषि भूमि के बीच नए सरकारी सर्वे नम्बर स्थित है जिनको कृषि भूमि के साथ दलालो ने मुख्य मार्ग से लगी हुई बता कर बेच दिया, यदि यहां के शासकीय नम्बरों की नपती की जाए तो सारा मामला पानी की तरह साफहो जाएगा कई सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे किये जा चुके हैं, और बिना कृषि भूमि को डाईवेशन किये या दिखावे के लिए मामूली डाईवेशन बता कर भूमि को सरकार भूमि के माध्यम से रोड से लगी हुई बता दिया गया है ।

सरकारी विभागों पर अतिक्रमणकर्ताओं की नजर, जानकारी होने के बाद भी विभाग नहीं लेता कोई एक्शन, भूमिका संदिग्ध

जमीन पर अतिक्रमण करने वाले दबंगो ने किसी भी मद की भूमि को नही छोड़ा , अतिक्रमणकर्ताओ ने सरकारी विभागों को आवंटित भूमि पर भी कब्जा कर लिया, मामला सोसाइटी गोदाम की भूमि बरवेट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिये आवंटित भूमि अतिक्रमणकर्ताओं के कब्जे में होने से सरकारी भवन नही बन पा रहे वही ग्राम करडावद में स्वास्थ्य विभाग और सोसाइटी को आवंटित शासकीय नम्बर पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया, अवैध कब्जों की वजह से नए निर्माण गाँव से दूर किये जा रहे हैं, ऐसा नही की विभाग प्रमुखों को इसकी जानकारी नही है। लेकिन वो जानकार भी अंजान बने बैठे हैं या यूं कहें कि स्थानीय कर्मचारियों और पदस्थ अधिकारीयो की मिलीभगत से भूमि को बेचा गया है, क्योंकि जिन विभागों की भूमि और अतिक्रमण है उस विभाग की और से अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्रवाई आज तक नही की गई।

भोपाल जा कर मुख्यमंत्री को की शिकायत, जांच के नाम पर अधिकारी कर रहे गुमराह

करड़ावद के युवाओं ने मामले में स्थानीय अधिकारियों से न्याय नहीं मिलने पर भोपाल प्रत्यक्ष जा कर मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और विभाग के प्रमुख सचिव से की थी। जहा मामला फिर से झाबुआ के अधिकारियों को ही भेजा गया जिन्होंने पूरे मामले में अतिक्रमण होने और उसे मुक्त करने के सम्बंध में कोई कार्रवाई नही की।

चोरी छिपे कर रहे थे बिजली चोरी, तीन घरों के मीटर हुए जप्त

माही की गूंज, थांदला।

वार्ड 5 मे स्थित मकान जहां से बिजली चोरी व मीटर से छेड़छाड़ के प्रकरण बनाए।

बिजली के अवैध उपयोग, बिजली चोरी रोकने के प्रयास मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की वज़िलेन्स टीम लगातार कर रही है। टीम को थांदला नगर के कुछ लोगो के यहां बिजली चोरी की शिकायत मिली थी, जिस पर विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने कार्यवाही कर मीटर जब्त किए। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण क्रमांक 6688 क्रमश 10,11,12,13 नगर के वार्ड क्रमांक 5 बोहरा गली के विद्युत उपभोक्ता मुर्तुजा नूरुद्दीन बोहरा, हुसैनी कुर्बान हुसैन बोहरा, मुस्तसिर अलीहुसेन, शब्बीर अली दाऊद बोहरा लंबे समय से मीटर से छेड़छाड़ कर चोरी की बिजली से घर रोशन कर रहे थे, यह चोरी गत वर्ष से उस समय से की जा रही थी जब बोहरा समाज के धर्म गुरु का नगर प्रवास हुआ था।

विद्युत वितरण कंपनी के जेई युवराज अवास्या ने बताया कि, गत दिवस इंदौर की सतर्कता टीम ने वार्ड क्रमांक 5 बोहर बाजार में शिकायत के आधार पर पंहुची थी कुछ घरों के मीटर की जांच की तो बिजली चोरी करना पाया गया, जिस पर टीम ने प्रकरण दर्ज कर मीटर जांच हेतु अपने साथ ले गयी।

अब देखना है कि, विजिलेंस टीम ने चोरी का प्रकरण बनाया हैं और समय भी बहुत हो चुका है ना ही चोरी करने पर कितना जुर्माना लगाया है इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ ना जानकारी दी या दोनों के बीच कोई सांठगांठ हो गई है

नगर में सम्भ्रांत परिवार द्वारा की जा रही बिजली चोरी का बड़ा प्रकरण प्रथम मर्तबा सामने आया।

नवोदय विद्यालय थांदला की कक्षा 6 टी प्रवेश हेतु आनलाईन पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

माही की गूंज,थांदला। विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती भावना शेल्के के निर्देश पर प्रवेश परीक्षा प्रभारी संतोष चौरसिया पीजीटी रसायन विज्ञान ने बताया कि, चयन परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर अब अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 कर दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय थांदला के अर्न्तगत मेघनगर, पेटलावद तथा थांदला तीनों विकासखण्डों में आने वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

पेटलावद, मेघनगर, थांदला ब्लॉक के अन्तर्गत समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा पांचवी के विद्यार्थियों द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय थांदला में प्रवेश हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आनलाईन कर सकते है।

कक्षा 6टी नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 30 अप्रैल 2022 को जवाहर नवोदय विद्यालय थांदला के अंतर्गत आने वाले विकासखंडो थांदला, मेघनगर एवं पेटलावद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। उक्त चयन परीक्षा में तीनों विकासखण्डों के कक्षा 5 वीं में सत्र 2021-22 में मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी भाग ले सकते है। जिनकी जन्म दिनांक 01.05.2009 से 30.04.2013 के मध्य हो।

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश की अवहेलना करता जनजाति विभाग

मानदेय में से कटता है शासकीय अवकाश का पैसा

माही की गूंज, झाबुआ/पेटलावद।

कोरोना काल से पूर्व कई अतिथि शिक्षक प्राथमिक, माध्यमिक व हाई स्कूल में कार्यरत थे। कोरोना की शुरुआत में लगे लॉकडाउन के बाद तो सरकार जैसे अतिथि शिक्षकों को भूल ही गई। परंतु जैसे ही डेढ़ वर्ष बाद दोबारा विद्यालय खुले तो फिर से सरकार को अतिथि शिक्षकों की याद आई और उन्हें उन्ही विद्यालय में आमंत्रित किया गया जंहा वह पूर्व में कार्यरत थे। जिसमें सबसे पहले हाई स्कूल फिर माध्यमिक स्कूल जिसके बाद अंतिम में प्राथमिक विद्यालयो में अतिथि शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित किए गए। हालांकि अतिथि शिक्षकों के विद्यालयों में इस सत्र मे कार्य करते हुए तकरीबन 3 माह या किसी का उससे भी ज्यादा समय हो चुका है लेकिन किसी का भी वेतन अभी तक उनके खातों में नही डाला गया है।

वेतन का हो रहा इंतजार

शासकीय विद्यालयों में अद्ययापन का कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों का वेतन हर माह नही डालते हुए करीब 3 से 4 माह में डाला जाता है। ऐसे में कई अतिथि शिक्षक अपने निवास से 5 किलोमीटर या उससे भी दूर अद्ययापन का कार्य करने जाते है। अभी भी कोविड काल के बाद स्कूल खुलने के बाद से वेतन अतिथि शिक्षकों को नही मिला है। ऐसे में किसी से भी उधार लेकर वे अपना गुजारा करने को मजबूर है। दीपावली से पहले लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने आदेश क्र. 2788, दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को जारी कर स्पष्ट आदेश दिया था कि, समस्त अतिथि शिक्षकों का वेतन दीपावली पर्व से पहले माह अक्टूबर 2021 तक के मानदेय का भुगतान किया जाए। आदेश में यह भी स्पष्ट था कि, अतिथि शिक्षकों के माह अक्टूबर 2021 तक के मानदेय की राशि जारी की जा चुकी है। लेकिन ये अतिथि शिक्षकों का दुर्भाग्य ही कहे कि, जनजाति विभाग लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश की अवहेलना कर रहा है, जिसका खामियाजा अतिथि शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है।

शासकीय अवकाश का भी काटा जाता है मानदेय

वैसे तो किसी भी शासकीय कर्मचारी का शासकीय अवकाश का भुगतान नही काटा जाता है। लेकिन मामूली वेतन पर नोकरी कर रहा या यूं कहें कि शिक्षा व्यवस्था को बनाये रखा हैं उन अतिथि शिक्षकों का छुट्टी का वेतन भी काटा जाता है, पेटलावद व बामनिया संकुल के कुछ अतिथि शिक्षक से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, नियमित शिक्षक की तुलना में अतिथि शिक्षक को कोई तवज्जो नही दी जाती है, जो पिछले सत्र में अतिथि शिक्षक थे उनका वेतन कभी भी पूरा नही दिया गया उसमे शासकीय अवकाश का मानदेय काटा जाता है।

मजबूरी का फायदा उठाती सरकार

सरकार की शिक्षा व्यवस्था की धुरी बन चुके अतिथि शिक्षक मामूली वेतन में नोकरी कर अपना घर चला रहा है। कई अतिथि शिक्षक ऐसे भी है जो मजबूरी में ये कार्य करने पर मजबूर हैं लेकिन सरकार अतिथि शिक्षकों के प्रति पूरी तरह से लापरवाह हो कर उनके हक व अधिकारों के लिए काम नही कर रही है। वही स्थानीय स्तर के अधिकारी भी सरकार के आदेशों को फाइलों में दबा कर उनका शोषण करने से बाज़ नही आ रहे हैं।

लोकशिक्षण संचालक भोपाल से जारी 26 अक्टुम्बर के आदेश के बाद भी जनजाति विभाग ने नही दिया मानदेय।

राज्य स्तर पर स्वर्णकार समाज महिला मंडल को किया पुरस्कृत

माही की गूंज,झाबुआ।

विगत दिनों सीहोर में आयोजित समाज के कार्यक्रम में झाबुआ स्वर्णकार महिला मंडल प्रदेश स्तर परं कोरोना काल में जन जागृति पैदा करने,समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने तथा समाज को आगे बढ़ाने के साथ ही समाज मे एकजुटता के माध्यम से समाज को एक रखने के लिए प्रदेश स्तर पर दूसरी बार पुरुस्कृत किया गया। समाज की महिला संगठन की प्रदेश सरंक्षक श्रीमती कुन्ता सोनी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती चंचला सोनी ने बताया कि, झाबुआ जिले के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती कुन्ता सोनी, माधवी सोनी, ममता सोनी ने सीहोर की पूरी टीम की प्रशंसा करते हुए सफल आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया । ज्ञातव्य है कि पूर्व में कोरोना काल में भी झाबुआ समाज की महिलाओ ने आयोजित प्रतियोगिताओ में भाग लेकर विजयी हुई थी उन सभी महिलाओं को ट्रॉफी प्रशस्ति पत्र एवं शाल ओढाकर सम्मानित किया गया। जिले की अध्यक्ष श्रीमती माधुरी सोनी को जिले में उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मानित किया गया तथा मास्क बनाने एवं वितरण के कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। दीपा सोनी को नृत्य मुद्रिका मे तथा उज्वला सोनी को नृत्य विधा के लिये प्रथम स्थान पाने पर पुरस्कृत किया गया। नृत्य प्रतियोगिता में अंजली सोनी प्रथम स्थान पर रही। इस अवसर पर कोरोना काल मे सेवा देने वाले सुमित सोनी को भी सम्मानित किया गया।

दुर्घटना के शिकार युवक ने मन्दिर की पेड़ी पर तोड़ा दम

माही की गूंज, बामनिया। यहां पेटलावद रोड स्थित खेड़ापति हनुमान मन्दिर के सामने एक युवक दुर्घटना का शिकार हो गया जहां उसकी मौके पर मौत हो गई। मंगलवार रात कालिया पिता भीमा खड़िया (32) निवासी तेजपुरा से पेटलावद की और जाते समय अपने दुपहिया वाहन से दुर्घटना का शिकार हो गया, युवक हनुमान मंदिर के सामने बनी पेड़ी पर गिरा जहाँ सर में गंभीर चोट लगने से युवक की मौके पर मौत हो गई। बामनिया चौकी से मौके पर पहुँची पुलिस ने युवक की पहचान कर हॉस्पिटल भेजा जहा उसे मृत घोषित कर दिया।

बंगाली डॉक्टर उतरा ब्याज के धंधे में, गरीब आदिवासियों से वसूल रहा 25 प्रतिशत का ब्याज

पचास हजार के दो लाख वसूलने के बाद तीन लाख की मांग, पुलिस के पास पहुँचा मामला

फर्जी डॉक्टर पंकज बिस्वास।

माही की गूंज, पेटलावद।

जिले में अवैध रूप से आए बंगाल और बांग्लादेसी लोग जो यहाँ आकर फर्जी डिग्री के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरी का पेशा कर गरीबो को लूट रहे है। यें कहा से और कैसे पहुँच कर फर्जी दस्तावेज बना लेते हैं इसका पूरा खुलासा भी माही की गूंज में सिलसिलेवार किया जा चुका है। सब कुछ स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों की जानकारी में आने और होने के बाद भी ÷दूध देती गाय को कौंन घर से निकाले÷ की तर्ज पर आज तक कोई कार्रवाई तो ठीक इनके दस्तावेजों की जांच तक नही हुई है। कई बाग्लादेसी व फर्जी डॉक्टर अब जिले के कई पंचायतो का हिस्सा होकर संपत्ति खरीद कर यही बस गए हैं और सिर्फडॉक्टरी पेशे से ही नही वरन् अब कई प्रकार के व्यापार के जरिए ग्रामीण आदिवासीयो को लूट रहे हैं।

पेटलावद थाने पर आई एक शिकायत के बाद खुलासा हुआ कि, ये बंगाली डॉक्टर 10 से 25 प्रतिशत की ब्याज दर से पैसे देकर लुट रहा है। अगर कोई विवाद नही हुआ होता तो इस गंभीर मामले का खुलासा नही होता और अवैध डॉक्टरी पेशे की आड़ में ब्याज बट्टे का काला कारोबार चलता रहता।

50 हजार के दिए दो लाख, तीन लाख की और मांग, नहीं देने पर लेनदार को पिट दिया

मामला सारंगी चौकी क्षेत्र का है, जहां डॉक्टर पंकज बिस्वास नाम का डॉक्टर अपनी दुकानदारी वर्षो से चला रहा है और अब ब्याज बट्टे का कारोबार शुरु कर दिया। ग्राम हनुमंतिया के कैलाश पिता गणपत मैंड़ा ने थाना और एसडीओपी पेटलावद को शिकायत दर्ज करवाई कि, सारंगी के बंगाली डॉक्टर पंकज बिस्वास से लेन-देंन का व्यवहार था और जरूरत पड़ने पर पचास हजार रुपए लिए थे और बाज़ार ब्याज वसूलने का वादा किया। लेकिन डॉक्टर अब तक मुझसे 50 हजार रुपये के बदले दो लाख रुपये वसूल कर चुका है, वही अब भी तीन लाख रुपए की मांग और कर रहा है। डॉक्टर 25 प्रतिशत की दर से ब्याज की वसुली कर रहा है और पैसे अब देने की हिम्मत नही है। लेकिन डॉक्टर आए दिन लोगो को लेकर घर आ जाता है और डरा-धमका कर पैसे की वसुली करने का बोलता है। यहां तक कि जिन लोगो को लेकर आता है उनका ओर पेट्रोल तक का खर्चा भी मुझ से वसूल करता है और रोज मारपीट की धमकी देता है।

कोई लेख पढ़ नहीं, डायरी में चलता है हिसाब

फरियादी कैलाश ने बताया कि, डॉक्टर पंकज जो भी रकम देता है इसकी कोई लेख पड़ नही करता है और जितनी राशि देता उसका ब्याज जोड़ कर राशि डायरी में लिख देता है, और समय पर पैसा नही आने पर उसमे भी ब्याज जोड़ कर वसुली करता है। इस डॉक्टर का अकेला मैं ही शिकार नही हु, क्षेत्र के कई ग्रामीणों को डॉक्टर, अपने जाल में फंसा कर 10 से 25 प्रतिशत का ब्याज वसूला जा रहा है।

क्लिनिक पर बुलाकर मारपीट व जान से मारने की धमकी

कैलाश मैड़ा ने बताया कि, 25 नवम्बर को डॉक्टर ने मुझे हिसाब करने के लिए क्लिनिक पर बुलाया और कहा कि, जो पैसे बता रहा हु वो भरते दे, पैसे तो देने ही पड़ेंगें। जिस पर कैलाश ने इतनी राशि नही देने का कहा तो डॉक्टर ने उसके क्लिनिक के बाहर लाकर मारपीट कर दी।

फरियादी कैलाश ने बताया कि, डॉक्टर ने जाती सूचक शब्दो से अपमान करते हुए मुझे जान से मारने और मरवाने तक की धमकी दी। मामले की शिकायत कैलाश द्वारा चौकी सारंगी पर लिखित रूप से की गई, लेकिन 4 दिन बाद भी कोई सुनवाई नही होने पर मामले की शिकायत एसडीओपी पेटलावद और थाना पेटलावद पर की है।

फरियादी कैलाश मैड़ा का कहना है कि, यदि यहाँ भी सुनवाई नही हुई तो एसपी साहब के पास जाकर मामले की शिकायत करूंगा।

स्वास्थ्य विभाग आखिर क्यों नहीं कर रहा कार्रवाई...?

वर्षो से जमे बैठे इन बंगालियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से इनके आगे नतमस्तक है। स्वास्थ्य विभाग अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए या फिर अवैध उगाही के लिए इन पर कोई कार्रवाई नही करता है। अब इनके चपेट में इलाज के नाम पर आते-आते ब्याज के इस अवैध धंदे में भी उतर कर भोले-भाले गरीबो को लूट रहे हैं। जिन पर सख्त कार्रवाई होना जरूरी है।

संपादकीय

सरकार की कानून वापसी, एमएसपी की मांग

आखिरकार देश के राजनीतिक व सामाजिक जीवन में भूचाल लाने वाले तीन कृषि सुधार कानूनों की वापसी पर संसद ने वैधानिक मोहर लगा दी। कृषि मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखे गए कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 ध्वनि मत से पारित हुए। हालांकि, विपक्ष कानूनों की वापसी पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा और एमएसपी आदि मुद्दों पर बहस करने के मूड में था। दरअसल, गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय संबोधन में इन कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था तथा संसद के शीतकालीन सत्र में वापसी की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने की बात कही थी। उम्मीद करें कि, अब सरकार की पहल के बाद किसान लचीला रुख दिखाते हुए आंदोलन वापसी पर गंभीरता से विचार करेंगे। हालांकि, किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। यद्यपि पिछले दिनों आंदोलनकारी किसानों ने आंदोलन की सालगिरह पर संसद तक ट्रैक्टर रैली निकालने के आह्वान को वापस लेकर सार्थक पहल की थी, लेकिन इस दिशा में गंभीर पहल जरूरी है। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री कह चुके हैं कि, एमएसपी के मुद्दे पर एक कमेटी बनाने का आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसमें विशेषज्ञों के साथ किसान प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। यह अच्छी बात है क्योंकि अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार एमएसपी के मुद्दे पर टालमटोल करेगी, लेकिन अब सरकार इस पर भी बात करने को तैयार है। उम्मीद है, किसानों के रुख में भी बदलाव आएगा।

इस टकराव के चलते देश ने भी बड़ी कीमत चुकाई है और दिल्ली के प्रमुख रास्ते बंद होने से जहां यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है, वहीं टोल बैरियर बाधित किये जाने से सरकार को रोज करोड़ों रुपये की चपत लगी है। वहीं बड़ी संख्या में किसानों को आंदोलन के दौरान हमने खोया है।

निःसंदेह, लंबे समय से एमएसपी से जुड़ी व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने की मांग उठती रही है। इस मुद्दे पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों का भी उल्लेख होता है, जिनका क्रियान्वयन नहीं हो सका। व्यावहारिक दिक्कत यह है कि, एमएसपी का लाभ चंद राज्यों में किसानों को ही मिल पाता है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तो जरूर करती है लेकिन व्यापारी एमएसपी पर फसल नहीं खरीदते। भंडारण क्षमता न होने और सिर पर चढ़े कर्ज के चलते किसान को फसल तैयार होने पर तुरंत औने-पौने दामों पर ही उपज बेचनी पड़ती है। ऐसे में एमएसपी सिस्टम को व्यावहारिक, पारदर्शी व लाभकारी बनाने की जरूरत है। मोदी सरकार भी कहती है कि, किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। उसे दुगना किया जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रभावी व कारगर फार्मूला लेकर सरकार को आना चाहिए। किसान को उसकी लागत के अनुरूप दाम मिलने ही चाहिए। कृषि श्रमिकों व उन किसानों को भी जिनका परिवार अपना श्रम फसल उगाने में लगाता है। निःसंदेह मेहनताना न्याय संगत ढंग से मिलना चाहिए। यह तथ्य छिपा नहीं है कि, लागत बढ़ने से किसान की मुश्किलें बढ़ी हैं। बिजली, डीजल, रासायनिक खाद व बीजों के दामों में वृद्धि तो हुई है लेकिन किसान का लाभ नहीं बढ़ा है। यह चिंता किसान आंदोलन में भी जुड़ गई थी। निःसंदेह, एमएसपी निर्धारण में इन तथ्यों का समावेश जरूरी है। इस बात में दो राय नहीं कि इन समस्याओं को संबोधित करते हुए सरकार व्यावहारिक तरीके से नीति निर्धारण करती है तो उसे किसानों का समर्थन भी हासिल होगा। यह भी हकीकत है कि, बढ़ती एमएसपी का बोझ देश के वित्तीय संसाधनों पर पड़ेगा। अब जब सरकार ने आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही और खेतों में पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है, किसानों को भी राष्ट्रीय सरोकारों को प्राथमिकता देते हुए उदार रवैया अपनाते हुए सदाशयता दिखानी चाहिए। किसानों व सरकार के बीच यह टकराव लंबा खिंचना देश के हित में नहीं होगा। यह कड़वाहटों को त्याग कर खुले मन से बातचीत की शुरुआत करके आगे बढ़ने का वक्त है।

चिंताजनक है जीका वायरस का हमला

देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही लगातार कमी देखी जा रही है लेकिन पिछले कुछ महीनों से देश के कई राज्यों में डेंगू के बढ़ते मामलों के साथ कुछ दिनों से जीका वायरस ने भी नई चिंता को जन्म दिया है। उत्तर भारत और खासकर उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के मामले जिस तेजी के साथ सामने आए हैं, उससे चिंता का माहौल बनना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, मथुरा सहित कई जिलों में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं और अब फतेहपुर जिले में भी जीका वारयस का केस सामने आने के बाद वहां स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला तो जीका वायरस और डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां जीका का पहला मामला 24 अक्तूबर को सामने आया था और उसके बाद से वहां पिछले करीब एक महीने में ही इसके 140 से भी अधिक मरीज सामने आ चुके हैं।

जीका संक्रमण को लेकर चिंताजनक स्थिति यह है कि, यह वायरस सामान्य लोगों के अलावा गर्भवती महिलाओं को भी संक्रमित कर रहा है। अब तक कई गर्भवती महिलाएं जीका वायरस से संक्रमित मिल चुकी हैं। इस वर्ष जीका वायरस का पहला मामला केरल में 8 जुलाई को सामने आया था, जिसके बाद केरल में जीका वायरस के मामले अचानक सामने आने लगे और ऐसे मामलों की संख्या 64 तक पहुंच गई थी। वहां जीका से एक मरीज की मौत की खबर सामने आई थी। महाराष्ट्र में भी जीका वायरस का मामला सामने आया था लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जीका का प्रकोप चिंता का सबब बना है। केरल के बाद अब उत्तर प्रदेश में जीका के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्पष्ट है कि, बारिश के बाद मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए सरकारी तंत्र द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए समुचित प्रबंध नहीं किए गए। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि, जहां शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में ही करीब 80 फीसदी लोगों को इस वायरस और इससे होने वाली बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वहीं ग्रामीण परिवेश में तो लोग इससे पूरी तरह अनजान हैं, इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक देशभर में कहीं ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया गया है, जिससे लोगों में जीका वायरस संक्रमण के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके।

आज भी देश में अधिकांश लोग नहीं जानते कि जीका आखिर है क्या, इससे क्या बीमारियां पैदा होती हैं और उनके क्या लक्षण सामने आते हैं। जीका एक खतरनाक वायरस है, जो उसी एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो डेंगू, चिकनगुनिया, निपाह, जापानी इन्सेफेलाइटिस, फाइलेरिया, मलेरिया इत्यादि बीमारियों का जनक है, यह मच्छर प्रायः दिन के समय सक्रिय रहता है। अधिकांशतः गर्भवती महिलाएं इस वायरस की शिकार बनती हैं। इससे गर्भपात और मृत बच्चे के पैदा होने का भी खतरा रहता है। यह जन्म लेने वाले बच्चे के विकास पर बहुत दुष्प्रभाव डालता है, इससे पीड़ित महिलाओं के बच्चे अविकसित दिमाग के साथ पैदा होते हैं। करीब 70 से 80 फीसदी मामलों में जीका संक्रमित व्यक्ति में लक्षणों की पहचान नहीं हो पाती, इसलिए जीका वायरस से बचने के लिए सबसे बड़ा हथियार जागरूकता को ही माना गया है।

जीका वायरस पर नियंत्रण के लिए दुनियाभर में अब तक कोई कारगर वैक्सीन नहीं बनी है। जो उपाय डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि फैलाने वाले मच्छरों से बचने के लिए बताए जाते रहे हैं, वही उपाय जीका वायरस फैलाने वाले मच्छर से बचने के लिए भी किए जाते हैं, जैसे अपने आस-पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, कहीं भी पानी को ठहरने न देना, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छरों की अधिकता वाले क्षेत्रों में पूरे कपड़े पहनना, मच्छरनाशक चीजों का इस्तेमाल तथा बगैर जांच के रक्त शरीर में न चढ़वाना इत्यादि। जीका वायरस से संक्रमित होने पर दर्द तथा बुखार की सामान्य दवाएं दी जाती हैं किन्तु लक्षण प्रबल होने पर विशेषज्ञ से परामर्श करना अत्यावश्यक हो जाता है। जीका वायरस खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके इंफैक्शन तथा उससे होने वाली बीमारियों का अभी तक कोई उपचार उपलब्ध नहीं है और कुछ मामलों में इससे लकवे के साथ मौत होने की संभावना भी रहती है।

योगेश कुमार गोयल

जीका वायरस गर्भवती मां से बच्चे में तथा शारीरिक संबंधों से भी स्थानांतरित होते हैं। इससे प्रभावित लोगों को हल्का बुखार, आंखों में संक्रमण, सिरदर्द, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकते इत्यादि लक्षण सामने आते हैं, जो प्रायः 2-5 दिन तक रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों में कई दिनों तक कोई लक्षण सामने नहीं आते। जीका वायरस से गुलियन-बार सिंड्रोम नामक नर्वस सिस्टम की बीमारी भी हो जाती है। इसकी अनुमानित मृत्यु दर 8 प्रतिशत से ज्यादा है। इस वायरस के संक्रमण से अस्थायी रूप से लकवा भी मार जाता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि, यदि जीका वायरस वीर्य में पहुंच जाए तो यह करीब दो सप्ताह तक जीवित रह सकता है और यही कारण है कि जीका वायरस के संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित यौन संबंध बनाने की सलाह दी जाती है और ऐसे क्षेत्रों में रक्तदान भी प्रतिबंधित किया जाता है।

जातिवाद कैसे खत्म करें?

सर्वोच्च न्यायालय ने इधर जातीय भेदभाव के आधार पर होने वाली हिंसा के बारे में कुछ बुनियादें बातें कह डाली हैं। जजों ने 1991 में तीन लोगों के हत्यारों की सजा पर मोहर लगाते हुए पूछा है कि, इतने कानूनों के बावजूद देश में से जातीय घृणा का उन्मूलन क्यों नहीं हो रहा है? अदालत की अपनी सीमाएं हैं। वह सिर्फकानून लागू करवा सकती है। वह खुद कोई कानून बना नहीं सकती। वह कोई समाजसेवी संस्था भी नहीं है कि, वह जातिवाद के विरुद्ध कोई अभियान चला सके। यह काम हमारी संसद और हमारे नेताओं को करना चाहिए लेकिन वे तो बेचारे दया के पात्र बने रहते हैं। उनका मुख्य काम है, वोट और नोट का कटोरा फैलाए रखना। उनमें इतना नैतिक बल कहां है कि उनके अनुरोध पर लोग अपने जातिवाद से मुक्त हो जाएं? उनकी दुकान चल ही रही है जातिवाद के दम पर !

डॉ. लोहिया ने जात-तोड़ो आंदोलन चलाया था लेकिन उनकी माला जपनेवाले नेता ही आज जातिवाद के दम पर थिरक रहे हैं। जातीय जन-गणना के शव को दफनाए हुए 90 साल हो गए लेकिन वे अब उसे फिर से जिंदा करने की मांग कर रहे हैं। 'मेरी जाति हिंदुस्तानी' आंदोलन की वजह से मनमोहनसिंह सरकार ने जातीय-गणना बीच में ही रुकवा दी थी लेकिन भारत में जातिवाद को जिंदा रखनेवाले 'जातीय आरक्षण' को खत्म करने की आवाज आज कोई भी दल या नेता नहीं लगा रहा है। देश में सरकारी नौकरी और शिक्षा में जब तक जातीय आधार पर भीख बांटी जाएगी, जातिवाद का विष-वृक्ष हरा ही रहेगा। मुट्ठीभर अनुसूचितों और पिछड़ों के मुंह में चूसनी लटकाकर देश के करोड़ों वंचितों और गरीबों को सड़ते रहने के लिए हम मजबूर करते रहेंगे। इस समय देश में जातिवाद के विरुद्ध जबर्दस्त सामाजिक अभियान की जरुरत है।

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

सबसे पहले जातिगत आरक्षण खत्म किया जाए। दूसरा, जातिगत उपनाम हटाए जाएं। तीसरा, किसी भी संस्था और संगठन जैसे अस्पताल, स्कूल, धर्मशाला, शहर या मोहल्ले आदि के नाम जातियों के आधार पर न रखे जाएं। चौथा, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाए। पांचवां, आम चुनावों में किसी खास चुनाव-क्षेत्र से किसी खास उम्मीदवार को खड़ा करने की बजाय पार्टियां अपनी सामूहिक सूचियां जारी करें और अपने जीते हुए उम्मीदवारों को बाद में अलग-अलग चुनाव-क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दें। इससे चुनावों में चलनेवाला जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। मतदाता अपना वोट देते समय उम्मीदवार की जाति नहीं, पार्टी की विचारधारा और नीति को महत्व देंगे। इसके कारण हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, जातीय आधार पर थोक वोट कबाड़नेवाले अपराधियों, ठगों, अकर्मण्य और आलसी लोगों से भारतीय राजनीति का कुछ न कुछ छुटकारा होगा।

टमाटर विमर्श के दौर में बाकी मुद्दे बेअसर

स्मार्ट विश्वविद्यालय ने टमाटर विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता निबंध इस प्रकार है, टमाटर का भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्व है। टमाटर का चुनाव में सरकार को कोसने के लिए, रसोई में सब्जी बनाने के लिए और कवि सम्मेलन में चाटू टाइप के कवियों पर प्रहार के लिए इस्तेमाल संभव है। राजनीति में हालांकि प्याज भी काम आता है और प्याज के सामने तो टमाटर जूनियर टाइप का ठहरता है पर टमाटर का अपना जलवा है। प्याज ने हालांकि सरकारों को बनाया और गिराया है, पर टमाटर भी अपने हिसाब से राजनीति में उठापटक पैदा कर सकता है। सौ रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचकर टमाटर ने अपनी हैसियत में जबरदस्त इजाफा किया है और अब यह पेट्रोल की संगत करने लगा है भावों के मामले में।

टमाटर किसी बंदे की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की हैसियत रखता है, सौ रुपए किलो के टमाटर के सामने अगर किसी बंदे की इच्छा आलू-टमाटर की सब्जी खाने की हो जाए, तो वह दिवालिया घोषित किया जा सकता है। आलू-टमाटर की सब्जी विलासिता लगे, यह हालात टमाटर के भाव पैदा कर सकते हैं। सौ रुपए किलो के भाव पर जब टमाटर पहुंच जाए, तो बंदा यह कह सकता है पुराने वक्तों में हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे और हमने भी कई बार टमाटर की सब्जी खाई है।

सांस्कृतिक योगदान तो टमाटर का अप्रतिम है। कवि सम्मेलनों में सड़े टमाटरों को हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करने का इतिहास रहा है। टमाटर सड़े हों, तो भी इन दिनों मिल नहीं रहे हैं। कई होटल रेस्टोरेंट सड़े टमाटरों से भी कामयाब सब्जी वैसे ही बना मारते हैं, जैसे बहुत घटिया बंदों से भी बड़े नेताओं का सृजन राजनीतिक दल कर लेते हैं।

आलोक पुराणिक

टमाटर चर्चा में है और चर्चा में रहेंगे, टमाटर का साहित्यिक महत्व यह है कि, यह व्यंग्यकारों के भी काम आ जाते हैं। टमाटर का बहुत बड़ा फायदा नेताओं को यह मिल जाता है कि, टमाटर के चक्कर में दूसरी समस्याओं पर ध्यान न जा पाता है। जैसे कोरोना का नया वैरियंट आ गया है- ओमीक्रॉन, पर इस पर भी पर्याप्त हल्ला न हो पा रहा है, क्योंकि अभी विमर्श टमाटर पर चल रहा है।

राजनीतिक दलों पर नकेल लगाना जरूरी

अब समय आ गया है कि, सत्ता पर काबिज होने के लिए विकास की बजाए मतदाताओं को मुफ्त बिजली-पानी, कंप्यूटर, स्कूटी और साइकिल के साथ ही मासिक भत्ता देने जैसे आर्थिक वादों को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण के दायरे में शामिल किया जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भ्रष्टाचार मिटाने का जोर-शोर से वादा करने वाले राजनीतिक दलों को इस दिशा में पहल करनी होगी और केन्द्र सरकार को मुफ्त रेवड़ियां देने जैसे चुनावी वादों को भ्रष्ट आचरण के दायरे में शामिल करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना होगा।

देश और प्रदेश के विकास तथा जन कल्याण की योजनाएं बनाने और उन पर अमल करने की बजाए आज राजनीतिक दल चुनावी वादों में मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं। सत्ता में आने पर कोई भी दल इस तरह के प्रलोभन देने वाले वादों पर अमल करता है तो इससे प्रदेश के राजस्व को ही नुकसान होगा और इससे विकास कार्यों में बाधा पड़ेगी।

ऐसी स्थिति से बचने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके यह प्रावधान करने पर विचार होना चाहिए कि, चुनाव के बाद सत्ता पर काबिज होने वाला दल अगर ऐसे आर्थिक प्रलोभन वाले चुनावी वादों पर अमल करता है तो इससे होने वाले राजस्व के नुकसान के एक हिस्से की भरपाई सत्तारूढ़ दल को करनी होगी, जिसमें प्रलोभन देकर मतदाताओं को लुभाने की प्रवृत्ति पर अंकुश संभव हो सकेगा।

पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा की जनता से इस समय किए जा रहे चुनावी वादे इस बात का संकेत हैं कि, देश की राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों का तेजी से ह्रास हो रहा है। राजनीतिक दलों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि, प्रदेश की जनसंख्या और राजस्व की स्थिति के मद्देनजर इन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा और इन पर प्रतिवर्ष कितना खर्च आएगा और प्रदेश की जनकल्याण योजनाओं का क्या होगा?

मतदाताओं को मुफ्त में रेवड़ियां देने के साथ ही अब मासिक भत्ता देने जैसे वादे समाज के सभी वर्गों को आकर्षित और प्रभावित करते हैं। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि ऐसे वादे लोकतंत्र की पवित्रता को प्रभावित करने के साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रक्रिया को खोखला कर रहे हैं। चुनाव घोषणा पत्रों में जनता से किए जा रहे वादे इस समय जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण के दायरे में नहीं हैं, लेकिन अगर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने की तरह ही चुनाव प्रक्रिया को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है तो इसके लिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है।

इस समस्या पर देश की शीर्ष अदालत भी चिंता व्यक्त कर चुकी है और उसने करीब आठ साल पहले जुलाई 2013 में अपने फैसले में कहा था कि, मुफ्त रेवड़ियां बांटने के वादे करने वाले राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने के लिए अलग से कानून बनाने पर विचार किया जा सकता है। विडंबना है कि, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने की जो जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है, उसे न्यायपालिका पूरा कराने का प्रयास कर रही है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपराधीकरण, बाहुबल और धनबल से मुक्त कराने में न्यायपालिका ने काफी हद तक सफलता पा ली है लेकिन अभी भी चुनाव सुधारों की दिशा में काफी कुछ करने की जरूरत है। निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका इस दिशा में प्रयास भी कर रही है लेकिन राजनीतिक लाभ-हानि को ध्यान में रखते हुए कई मुद्दों पर सर्वदलीय बैठकों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की इन पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। न्यायपालिका की सख्त टिप्पणियों के बावजूद राजनीतिक दलों में देश और प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और राजस्व को हानि पहुंचाने वाले वादे करके मतदाताओं को प्रलोभन देने की होड़ लगी है।

न्यायालय ने 2013 में निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि, चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू होने वाली आदर्श आचार-संहिता में अलग से राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों के संबंध में भी प्रावधान किया जाये।

अनुप भटनागर

न्यायालय के निर्देश के बाद निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार-संहिता में एक नया उपबंध शामिल किया, जिसमें मतदाताओं को प्रभावित करने वाली तमाम घोषणायें करने पर प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन राजनीतिक दलों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वे आज भी मुफ्त सुविधाएं देने ही नहीं, बल्कि मासिक भत्ता देने जैसे वादे कर रहे हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए टेलीविजन, मंगलसूत्र, प्रेशर कुकर और ऐसी ही दूसरी वस्तुएं देने के वादे का सिलसिला 2006 में तमिलनाडु से शुरू हुआ। इसके बाद मतदाताओं को आईफोन देने, घर देने जैसे भी वादे किये जाने लगे। लेकिन धीरे-धीरे यह बीमारी दूसरे राज्यों में भी फैल रही है और यहां मतदाताओं को लुभाने के लिए बिजली-पानी, स्कूटी, लैपटॉप और महिलाओं को एक हजार रुपये महीने का भत्ता, महिलाओं को निःशुल्क यात्रा और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने तक के वादे किये जा रहे हैं। अब इस बीमारी का इलाज जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन ही नजर आता है।

लव जेहाद की शिकार होने से बची रिया

रायपुर की रिया को हिन्दू संगठन व पुलिस के माध्यम से परिवार को किया सुपुर्द

फर्जी परिचय पत्र तैयार करने का गंभीर मामला आया सामने

माही की गूंज, रतलाम।

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अमेठी नई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दीपिका सिंह डोडिया के नेतृत्व में जावरा में मध्यप्रदेश शासन के मंत्री बिसाहूलाल द्वारा महिलाओं को लेकर आपत्ति जनक टिप्पणी करने के विरोध में मंत्री बिसाहू लाल को मंत्री पद हटाने की मांग ओर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग को लेकर जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन दिया गया। साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि, जल्दी मंत्री को पद से इस्तीफा दिया जाए अन्यथा मध्यप्रदेश में खुलकर विरोध किया जाएगा। साथ ही जावरा के एक मुस्लिम युवक इमरान द्वारा रायपुर की एक राजपूत बेटी को सोशल मिडिया के माध्यम से लव जिहाद का शिकार बनाने के विरोध में भी एसडीएम को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि, जावरा शहर मे ऐसी कई देश विरोधी गतिविधियां कूछ असामाजिक तत्वों द्वारा संचालित की जा रही है। जिसकी जल्दी जांच कर अपराधियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई।

युवक ने खुद की वोटर आईडी को एडिट कर युवती का फोटो लगाकर आयेशा नाम से बनाई फर्जी वोटर आईडी

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की रहने वाली 19 वर्षीय युवती से जावरा के एक 35 वर्षीय युवक ने सोशल मीडिया पर अपना नाम बदल कर दोस्ती की थी, ओर उसे बहला-फुसलाकर होशंगाबाद जाते वक्त इटारसी स्टेशन से अपनी बाइक पर लेकर निकला। वहीं पीड़िता की मां ने इटारसी जीआरपी थाने में शिकायत करने के साथ ही हिंदू संगठन को पत्र लिखकर मदद मांगी। जिस पर लव जिहाद की संख्या में संगठन ने दबाव बनाया तो इटारसी पुलिस हरकत में आई और रतलाम की पुलिस की मदद से युवती को बांसवाड़ा (राज.) से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वही अब तक जांच में पता चला है कि, लड़के ने खुद की वोटर आईडी एडिटिंग करते हुए उस पर युवती का फोटो लगा दिया और नाम भी एडिट करते हुए आयेशा खान निवासी जावरा करवा लिया। हालांकि युवती मिलने के बाद लव जिहाद या अपहरण जैसा कोई मामला पुलिस ने दर्ज नहीं किया, लेकिन वोटर आईडी एडिटिंग को लेकर पुलिस जांच कर रही है।

वही अखिल भारतीय महिला शक्ति महासभा द्वारा जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति को ज्ञापन देकर मांग की गई कि, जल्दी से जल्दी इसकी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह देवड़ा ने बताया कि, सूचना मिलने के बाद हिंदू जागरण समिति के महामंत्री नेपाल सिंह डोडिया ने पुलिस से संपर्क किया और डीएसबी शाखा की मदद से युवक को ट्रेस किया। इस बीच इटारसी जीआरपी थाना प्रभारी वीवी टांडीया भी जावरा पहुंचे ओर रतलाम पुलिस की मदद से युवक की अगली लोकेशन बांसवाड़ा जिले में मिली तो इटारसी पुलिस वहां गई और युवती को युवक की रिश्तेदार के यहां से बरामद करके इटारसी पुलिस ने परिजनों की सुपुर्द किया।

वहीं पुलिस ने बताया कि, युवती ने कोई आपत्तिजनक बयान दर्ज नहीं कराया इसलिए एफआईआरदर्ज नहीं हुई है। अन्य दस्तावेज से छेड़छाड़ को लेकर मामला जांच में चल रहा है। वही हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों के मुताबिक जिस युवक ने यह कारस्तानी की है वह पहले तो शादीशुदा है और जावरा में किसी बड़े न्यूज़ चैनल प्रतिनिधि के साथ कैमरामैन का काम भी करता है। एसड़ीएम कार्यालय पर ज्ञापन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष दीपिका सिह व जिला अध्यक्ष सीमा कंवर देवड़ा, जिला मीडिया प्रभारी रीना कुँवर सिसोदिया, जिला अध्यक्ष कविता कुँवर चौहान, नेहा कुँवर सिसोदिया, दीपमाला, सोना कुँवर, वर्षा कुँवर, सुमन कुँवर, महिमा, कविता, हेमलता, मोनिका, उपस्थित रहे।

इनका कहना है

महिला मध्यप्रदेश अध्यक्ष दीपिका सिंह राजपूत का कहना है कि, जिस व्यक्ति द्वारा रायपुर की रिया को अपनी बाइक पर बिठाकर जावरा लाना और जावरा से फिर बांसवाड़ा ले जा ले जाना और हिंदू लड़की को मुस्लिम नाम से फर्जी आईडी बनाना इसकी जांच होना चाहिए। लड़की के परिवार को बहुत ज्यादा डराया और धमकाया होगा, जिससे उसने कोई गलत बयान नहीं दिया, जिसकी भी जांच निष्पक्ष की जाना चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता इसमें कहीं न कहीं अन्य लोग भी शामिल है जिसकी जांच कर उन पर भी कार्रवाई की जाए।

जावरा एसडीएम दिमांशु प्रजापति ने बताया, फर्जी वोटर आईडी को लेकर हमारे द्वारा भी जांच की जा रही है और जावरा सीएसपी द्वारा भी इस मामले में जांच की जा रही है। वही हिन्दू लड़की का नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखने को लेकर भी जांच चल रही है जल्दी कार्रवाई को जाएगी। जो सहयोगी है उनके ऊपर भी मामला पंजीबद्ध किया जाएगा।

गांधी सागर अभ्यारण में हो रही बाघों की गणना

माही की गूंज, भानपुरा।

जिले के गांधीरसागर अभ्यारण्य में एक से सात दिसंबर तक वन्य प्राणी बाघ की भी गणना हो रही है। इसे लेकर वन विभाग द्वारा लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। वन्य प्राणियों की गणना के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण भी कुछ माह पहले दिया गया था। इसमें प्राणियों की गणना की तकनीक बताई गई थी।

रेंजर पन्नालाल रायकवार ने हुए बताया कि, गांधीसागर अभ्यारण में वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ रही है। वन विभाग द्वारा वैज्ञानिक तरीके से भी वन्य प्राणियों नजर रखी हुई है। सामान्य वन मंडल मंदसौर के अंतर्गत गांधीसागर अभ्यारण्य में एक से सात दिसम्बर तक वन्य प्राणियों की गणना होगी। वनमंडलाधिकारी विजयसिंह एवं अधीक्षक एसके अटोदे मार्गदर्शन में अभ्यारण्य क्षेत्र के वनों में वन्य प्राणियों की गणना होगी।

कर्मचारियों को दिया गया दो दिवसीय प्रशिक्षण

इस गणना को लेकर वनविभाग के वरिष्ट अधिकारियों ने भारतीय वन्यप्राणी संस्थान देहरादून के वन्य जीव विशेषज्ञ डब्ल्यूडब्ल्यूएफके सदस्य एवं राज्य वन अनुसंधान जबलपुर के सदस्यों द्वारा 17 एवं 18 अगस्त को गांधीसागर में सघन प्रशिक्षण कार्यकम में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रोजेक्टर द्वारा फील्ड मे जाकर मांसाहारी एवं शाकाहारी वन्य प्राणियो की गणना के प्रकार एवं उनके पदचिन्हों के बारे में दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था। उसी के तहत सात दिवसीय वन्यप्राणी गणना मोबाइल एप के जरिए की जाएगी होगी। इस गणना में स्थानीय तथा मंदसौर एवं नीमच जिला स्तर के प्रशिक्षित स्टॉफको शामिल किया गया है। रेंजर श्री रायकवार ने बताया कि, गणना के साथ ही अभ्यारण्य में मौजूद वन्य प्राणियों के सुरक्षित आवास एवं आहार पर भी मुख्य रुप से ध्यान दिया जाएगा।

सख्त हुए कलेक्टर...

तहसीलदारों को परफॉर्मेंस सुधारने की दी चेतावनी

आगामी बैठक में सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले दो तहसीलदार होंगे निलंबित

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के राजस्व अधिकारियों की कार्य समीक्षा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा बैठक आयोजित की गई। विभिन्न राजस्व मुद्दों पर कलेक्टर द्वारा कई राजस्व अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए खासतौर पर तहसीलदारों को परफारमेंस सुधारने के लिए चेतावनी दी। कलेक्टर ने यह स्पष्ट कहा कि, आगामी राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान सबसे खराब परफॉर्मेंस पाए जाने वाले जिले के दो तहसीलदारों को निलंबित किया जाएगा। साथ ही संबंधित एसडीएम को शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर एमएल आर्य, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार अधीक्षक भू-अभिलेख, नायब तहसीलदार उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व वसूली की समीक्षा की। जावरा तहसीलदार द्वारा कम वसूली किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की, साथ ही एसडीएम को भी समीक्षा करने के निर्देश दिए। रतलाम शहर में भी तहसीलदार द्वारा कम वसूली की गई जिस पर कलेक्टर द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया।

राज्य शासन के अभिलेख शुद्धीकरण अभियान की भी समीक्षा कलेक्टर ने की बताया कि, जिले के ताल, आलोट में अच्छा कार्य किया गया है, जिसकी कलेक्टर द्वारा सराहना की गई। भूमि स्वामी प्रकार में रतलाम तहसील पीछे हैं तो रिक्त भूमि स्वामी मद में पिपलोदा, सैलाना द्वारा अच्छा कार्य नही किया गया। मूल एवं बटन खसरा में रावटी, जावरा, सैलाना, पिपलौदा का कार्य असंतोषजनक है। सीमांकन तथा नामांतरण प्रकरणों की भी समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। कलेक्टर ने साफनिर्देश दिए कि, आगामी बैठक से पूर्व 300 दिवस से ज्यादा की राजस्व शिकायतों का निराकरण कर दिया जाए। बैठक में धारणाधिकार स्वामित्व योजना की भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश तहसीलदारों को दिए। नजूल निर्वतन की भी समीक्षा की। खनिज पट्टों के भौतिक सत्यापन की समीक्षा भी की गई। इसमें लगभग सभी तहसीलदारों के द्वारा कार्य नहीं किए जाने पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। लोक सेवा गारंटी की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि, सैलाना में शिकायतें क्यों बढ़ रही है अपर कलेक्टर को समीक्षा के निर्देश दिए।

आम आदमी पार्टी ने मनाया पार्टी स्थापना दिवस

माही की गूंज, शाजापुर।

संविधान दिवस पर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर को याद करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम्बेडकर चौराहे पर बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और संविधान दिवस की एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओ ने एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। वार्ड नं एक के संभावित उम्मीदवार अनिल कदम ने बताया कि, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के 9 साल बेमिसाल दिए है। आज हम सब के लिए गर्व की बात है कि आम आदमी पार्टी डॉ. भीमराव आंबेडकर के सपनो का भारत बनाने की और बड़ रही है। जहां सब बराबर और सबका विकास संविधान अनुरूप हो, सबके हक अधिकार सबको संविधान अनुरूप मिले यही सपना आम आदमी पार्टी का है। जो वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जन कल्याण, मूलभूत निःशुल्क सुविधाये, बिजली, पानी, महिला यात्रा, राशन आदि सभी सुविधाए निःशुल्क देकर जनकल्याण कर रही है। हम भी उसी मार्ग पर डॉ भीमराव आंबेडकर का भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज सभी सम्मानिय देशवासियों को हम संविधान दिवस और आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस कि बधाई और शुभकामनाएं देते है।

इस अवसर पर सुनील कदम ने बताया कि, हम राजनीति में राजनीति करने नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने आए हैं। दिल्ली मॉडल पूरे देश में लागू होगा गरीब वर्ग के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और मूलभूत सुविधाएं सहज उपलब्ध होंगी। हम शाजापुर को ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका तक सुधार के लिए तैयार है। अब जनता को समझना होगा कि ईमानदार प्रशासन को चुनना है या बेईमानो को। इस अवसर पर सुनील कदम, अनिल कदम, वकील खान, राजेश गुप्ता, अर्जुन जाटव, विजय जाटव, किशन लाल जाटव, जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिसनोरिया आदि अनेक लोग उपस्थित रहे।

जिले में नही है खाद की कमी- कलेक्टर जैन

माही की गूंज, शाजापुर।

सोशल मीडिया एवं अलग-अलग चैनल्स से चल रही खबर कि शुजालपुर में उर्वरक की कमी है और इस कारण विवाद हो रहा है का खण्डन करते हुए कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि, शुजालपुर में उर्वरक की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में भण्डारण है और किसानों को वितरित किया जा रहा है। सोसायटी में हुए विवाद के संबंध में कलेक्टर ने बताया कि, उर्वरक लेने आए लोगों में आपस में मारपीट हुई है और दोनों ने एक-दूसरे के विरूद्ध थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है।

कलेक्टर श्री जैन ने बताया कि, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था शुजालपुर में हुए विवाद की सूचना पाकर स्थानीय तहसीलदार राकेश खजुरिया द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें पाया गया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था शुजालपुर सिटी में ग्रामीणों द्वारा लाईन लगाकर खाद लिया जा रहा था, कि अचानक लाईन में लगे व्यक्तियों में धक्का-मुक्की हो गई और ग्राम मण्डावर के पृथ्वी पुत्र ज्ञानसिंह परमार (21) तथा ग्राम भीमपुरा के जितेन्द्र पिता रमेश धनगर (32) का आपस में झगड़ा हो गया। आपसी लड़ाई में चाटे एवं डण्डे से मारपीट होना बताया गया है। कलेक्टर ने बताया कि, इसमें खाद की समस्या को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ है। आपस में मारपीट की थाने में एफआईआर हुई है और आरोपी और फरियादी की एमएलसी भी हुई है, जिसमें सामान्य चोटें है। अन्य कोई बात जांच में नहीं पाई गई है।

खाद की कोई समस्या नहीं है। खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है।

मंडी में प्याज के गिरे दाम, किसानों में नाराजगी

माही की गूंज, मंदसौर।

प्याज के दामों ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। एक सप्ताह पहले प्याज के भाव एक हजार 800 से 2 हजार 400 रुपए प्रति क्विंटल तक किसानों को मिल रहे थे। लेकिन अब दामों में भारी अंतर आ गया है। मंगलवार को प्याज के दामों में बड़ी गिरावट होने से किसान नाराज हो गए। दाम कम मिलने से मंडी में किसानों ने नाराजगी भी व्यक्त की।

किसानों का कहना है कि, प्याज के दाम इतने कम हो गए है कि लागत भी नहीं निकल रही है। एक सप्ताह पहले मंडी में प्याज के अधिकतम भाव किसानों को एक हजार 800 से 2 हजार 400 रुपए तक मिल रहे थे। जबकि मंगलवार को किसानों को न्यूनतम 200 से अधिक एक हजार 499 रुपए प्रति क्विंटल मिले। अधिकांश किसानों के प्याज 700 रुपए से एक हजार 200 रुपए तक ही बिके। एक सप्ताह में लगभग एक हजार रुपए की गिरावट होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। मंगलवार को प्याज की नीलामी में एक हजार 500 रुपए क्विंटल तक भी उच्चतम भाव नहीं पहुंचे। प्याज के लाभकारी दाम नहीं मिलने से किसानों ने मंडी में नाराजगी जताई।

जमीन तलाशते मेडिकल कॉलेज को कैबिनेट से मिली मंजूरी

माही की गूंज, मंदसौर। साहिल अगवान

लंबे समय से चल रही मन्दसौर मेडिकल कॉलेज की मांग को मंगलवार को मध्यप्रदेश कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। जिले में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए 270 करोड़ 59 लाख की राशि मंजूर हुई है। जानकारी अनुसार, केंद्र सरकार ने 2020 में देश भर के अलग-अलग हिस्सों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। इन मेडिकल कॉलेज के निर्माण में 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40 फीसदी राशि राज्य सरकार को देना होगी। देशभर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा के साथ ही मन्दसौर में मेडिकल कॉलेज का रास्ता भी साफ हो गया था। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए राशि को मंजूर किया था इसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण में देरी हुई। लेकिन अब शिवराज सरकार के कैबिनेट में हुए फैसले से मन्दसौर को बड़ी सौगात मिल गई है। अब मंदसौर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है।

जमीन तलाशने में बिता दिया पूरा वर्ष

केंद्र सरकार की 2020 में हुई घोषणा के बाद जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित करने में ही प्रशसन और जनप्रतिनिधयों को पूरा एक वर्ष का वक्त लग गया। पहले संजीत रोड क्षेत्र में जमीन चिन्हित की गई थी इसका विरोध शुरू हुआ तो बाद में फोर लेन हाईवे से लगे बायपास पर मेडिकल कॉलेज के लिए 7.142 हेक्टर भूमि चिन्हित की गई। हाईवे के से लगे आरटीओ कार्यालय, पुलिस क्वार्टर और हॉकी मैदान के पास तीन हिस्सों में मेडिकल कॉलेज की भूमि चिन्हित की गई है। एक हिस्से में डॉक्टरों और स्टाफ के लिए रिहायशी मकान बनाए जाएंगे, जबकि दूसरे हिस्से में मेडिकल कॉलेज बनेगा।

मन्दसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि, भूमि की डीपीआर से लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर इस बड़ी योजना की शुरुआत करेंगे।

जिले के साथ राजस्थान को भी मिलेगा लाभ

मन्दसौर मेडिकल कॉलेज का लाभ मन्दसौर जिले के साथ मध्यप्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों को भी मिलेगा। अब तक, मन्दसौर जिले और आसपास के लोगों को इलाज के लिए इंदौर, उदयपुर या अहमदाबाद जाना पड़ता था। लेकिन जिले में मेडिकल कॉलेज की सौगात के साथ अब जिले के साथ राजस्थान के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

दस किलो गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, सीतामऊ।

तितरोद दरवाजा खाती मोहल्ले में एक गुमटी पर पुलिस ने दबिश दी। यहां से 10 किलो गांजा जब्त कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित द्वारा यहां अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा था, वह 100-100 रुपए में गांजे की पुड़िया बेचता था।

सीतामऊ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने बताया कि, सीतामऊ में तितरोद दरवाजे के पास स्थित गुमटी पर हीरालाल पुत्र भावनदास सिंधी निवासी तितरोद दरवाजा खाती मोहल्ला द्वारा गांजा अवैध रूप से बेचा जा रहा था। गुमटी की तलाशी लेने पर आरोपित हीरालाल के कब्जे से प्लास्टिक के कट्टे में कुल 10 किलो ग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि, आरोपित हीरालाल सिंधी से पूछताछ की जा रही है कि वह गांजा कहां से लाया है। आरोपित के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपित ने बताया है कि, आरोपित लम्बे समय से अवैध रूप से गांजे का विक्रय कर रहा है, गांजा 100-100 रुपए की पुड़िया बेचता है।

गलत साइड से आ रहे तेज रफ़्तार डम्फर से टकराई कार, चार घायल एक गंभीर

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में यातायात के नियमो की अनदेखी के चलते इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि सामने आ रही है। जिले के नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना घटित हो गई। जहा गलत साइड से आ रहे एक तेज रफ़्तार डम्फर ने एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में चार लोग घायल हुए है। वही एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी अनुसार नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत धौंसवास के समीप फोरलेन पर मंदसौर की तरफसे एक तेज रफ़्तार डम्फर रॉन्ग साइड जा रहा था, वही मन्दसौर की ओर से आ रही कार डम्फर से टकरा गई। इस दौरान कार में सवार सुधिधा पिता संजय (21), ऋतू पिता अजय (26), सयंम पिता संजय (25) और विभा पति संजय (50) घायल हो गए।

सूचना मिलते ही नामली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेन्स की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया।

मुख्यमंत्री ने काइसेंस मैनेजमेंट समूह को किया संबोधित

माही की गूंज, अलीराजपुर। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश भर के काइसेंस मैनेजमेंट समूह के सदस्यों, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मैदानी अमला व आमजन को संबोधित करते हुए कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश में कोरोना से बचाव हेतु पूर्व से विशेष प्रयास करने की बात कही। उन्होंने समस्त काइसेंस मैनेजमेंट समूह सदस्यों से आह्वान किया कि, कोरोना का नया वेरिएंन्ट देश प्रदेश में अभी कही भी पाया नहीं गया है लेकिन सावधानी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि, रोको-टोको अभियान के तहत मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन, हाथों को थोडे-थोडे समय में सेनेटाइज करने तथा टीके की दोनों डोज लगाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए।

अलीराजपुर जिले में मुख्यमंत्री श्री चौहान के संबोधन को कलेक्टोरेट कायार्लय स्थित वीसी कक्ष में सुना और देखा गया। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, मुख्य कायर्पालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती संस्कृति जैन, विधायक अलीराजपुर क्षेत्र प्रतिनिधि श्री खुर्शीद अली दीवान, किशोर शाह सहित अन्य समूह सदस्यगण उपस्थित थे।

40 क्विंटल सोयाबीन चोरी मामले में पुलिस ने नहीं की एफआईआर दर्ज

थाने पर पहुंचे परिजन, रायपुरिया थाना प्रभारी ने परिजनों को धमकाया

माही की गूंज, पेटलावद।

भांझगड़ी तो कभी रिकार्ड दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अपराध दर्ज नही करती ये कोई नई बात नही है। लेकिन पुलिस की अपराध दर्ज नही करने की पॉलिसी के कारण अपराध का शिकार लोग ही प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। रायपुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बरवेट में 12 नम्वबर को हुई 40 क्विंटल सोयाबीन कीमत दो लाख रुपये की हुई चोरी मामले में थाना रायपुरिया में प्रकरण दर्ज नही होने से भड़के परिजन थाना रायपुरिया पहुच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लेकिन थाना प्रभारी ने परिजनों को धमकाते हुए उन पर ही मामला दर्ज करने की धमकी दे डाली, इतना ही नही थाना प्रभारी ने मामले को फर्जी बता कर परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।

ये है मामला

ग्राम बरवेट निवासी अमृतलाल पाटीदार के चंपेलिया रोड स्थित पुराने मकान से 11 नवम्बर को अज्ञात बदमाशों द्वारा पीछे का दरवाजा तोड़ कर कमरे मे रखे 40 क्विंटल सोयाबीन चोरी हो गये। जिसकी सूचना अमृतलाल पाटीदार द्वारा थाना रायपुरिया पर दर्ज कराई गई पुलिस ने मौके पर पहुँच कर जांच भी की लेकिन घटना के 20 दिन बाद भी पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज नही किया।

परिजन पहुंचे थाने थानेदार ने धमकाया

मामले में 20 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नही होने के चलते परिजनों ने थाना रायपुरिया पहुँच कर एफआईआर दर्ज नही करने के कारण पूछे, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत की तर्ज पर थाना प्रभारी ने परिजनों को मामला फर्जी होने का बोलते हुए नेता गिरी करने का आरोप लगाते हुए, झूठी शिकायत के मामले में आप पर मामला दर्ज हो सकता कि धमकी दे डाली। वारदात के शिकार परिवार के सदस्य जीवन पाटीदार ने बताया कि, थाना प्रभारी चोरी का मामला दर्ज करने की बजाए परिजनों को धमका कर चोरी कैसे हो सकती है बोल कर डराने पर उतारू हो गया, जब हमारे द्वारा थाना प्रभारी को कहा गया कि, हम सभ्य और सम्पन्न परिवार के लोग हैं हमको झूठी शिकायत करने से क्या फायदा ओर आपकी जांच में शिकायत झूठी हो तो हम पर भी अपराध दर्ज कर लेना कहा गया। तब कही जा कर थाना प्रभारी ने अपने सुर बदले। थाना प्रभारी ने हमारे सामने अधिकारीयो को फोन लगा कर बताया कि, ये झूठी शिकायत कर रहे है और ये वही लोग हैं जो ऊपर से शिकायत कर फोन लगवा रहे हैं। रायपुरिया पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज़ पीड़ित के परिजन बिना एफआईआर खाली हाथ लौट गए।

अमृतलाल पाटीदार ने बताया कि, पुलिस चोरी के बाद मौके पर आई और सब कुछ अपनी आँखों से देख कर गई अब पुलिस चोरी की घटना होने से बदल रही है ,अगर यहाँ सुनवाई नही हुई तो इसकी आगे शिकायत करेगें ।

आरोपी को हथकड़ी लगाने के वीडियो वायरल मामले में 3 पुलिसकर्मी निलंबित

माही की गूंज, अलीराजपुर।

थाना जोबट के अपराध क्रमांक 354/2021 धारा 420 ए, 409 भादवि में उप जेल जोबट में निरुद्ध आरोपी अनुप वाणी निवासी जोबट के पुलिस रिमांड के दौरान शासकीय अस्पताल जोबट में मेडिकल परीक्षण कराने हेतु हथकड़ी लगाकर प्राइवेट वाहन में थाना जोबट में तैनात पुलिस अधिकारी व कमर्चारियों के द्वारा लाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिस पर एसपी मनोज कुमार सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वायरल वीडियो का सूक्ष्मता से अवलोकन कर पाया कि, आरोपी को पुलिस जवानों द्वारा प्राइवेट वाहन में हथकड़ी लगाकर लाने पर विवाद परिलक्षित हो रहा है। जो पुलिस अधिकारी व कमर्चारी की लापरवाही को प्रदशिर्त करता है। जिस पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 31 तथा पुलिस रेगूलेशन के पैरा क्रमांक 64 के नियम दो एवं तीन में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त लापरवाही के लिए एसपी ने उप निरीक्षक सुनील रंधेए आरक्षक क्रमांक 396 फक्कीरचंद एवं आरक्षक क्रमांक 498 जगदीश सभी तैनात जोबट थाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उक्त सभी का मुख्यालय रक्षित केंद्र अलीराजपुर रहेगा तथा नियमित रूप से रोल कल में उपस्थित रहेंगे। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निवार्ह भत्ते की पात्रता रहेगी।

वहीं पुलिस ने उक्त प्रकरण में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, पुलिस अनुसंधान के दौरान चिल्लाचोट करने, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करने, अभद्रता करने पर अनुप पिता दिनेश वाणी, योगिता पति अनूप वाणी, जितेंद्र पिता घनश्याम वाणी, कीतिर्श पिता घनश्याम वाणी, दिनेश पिता मदनलाल वाणी, कुलदीप पिता राजेंद्र वाणी सभी निवासी जोबट पर अपराध क्रमांक 353ए, 332ए, 186ए, 34 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने जिले के समस्त पुलिस अधिकारी एवं कमर्चारियों को सख्त हिदायत दी है कि, पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ पेश आए तथा किसी भी तरह से हठधमिर्ता बरदात नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने समस्त आमजन को भी आह्वान किया है कि, वे शासकीय कार्य में अनावश्यक रूप से बाधा नहीं डाले। शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्ती से कार्रवाई सुनिचित की जाएगी।

बस स्टेंड की बिगड़ती व्यवस्थाओं पर किसी का नहीं है ध्यान

बेतरतीब खड़े वाहनों और बसों से हो जाती है गुत्थम-गुत्था

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला मुख्यालय का बस स्टेंड इन दिनों बदहाल व्यवस्थाओं का शिकार है। जब जहां जिसकी जैसी मर्जी हो वाहनों को बस स्टेंड पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। चूंकि बस स्टेंड के आसपास शैक्षणिक संस्थाएं भी है तो स्कूलों की छुट्टी होने के समय बस स्टेंड की तस्वीर बहुत ही भयावह दिखाई देने लगती है। जिला मुख्यालय से गुजरने वाली बसें भी बस स्टेंड पर बेतरतीब ही खड़ी कर दी जाती है। इसके अलावा अन्य छोटे वाहन भी मुख्य बस स्टेंड पर ही पार्क कर दिए जाते है। ऐसा नहीं है कि बस स्टेंड की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पहले कोई प्रयास नहीं किए गए। मगर समस्या को सुलझाने के लिए कोई प्रभावी व ठोंस कदम भी नहीं उठाए गए। व्यवस्थाओं को सुधारने के बाद कुछ में ही स्थिति वापस ''ढाक के तीन पात'' सी हो जाती है।

हालांकि बस स्टेंड की व्यवस्थाओं में हमेशा तब्दीली आती रही है। मगर इसके सुधार को लेकर किसी तरह का कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। यातायात अमला व जिम्मेदार अधिकारी अब तक यहां नित नए प्रयोग करते हुए है और बस स्टेंड को फुटबाल

बनाते रहे है। कभी किस तरफ बसों को खड़े करवाना, कभी किस तरह। हमेशा बसों के खड़े रहने के स्थान को परिवर्तन कर फुटबाल की तरह यहां से वहां करना, बावजूद इसके किसी तरह के गोल पर नहीं पहुंच पाना अधिकारियों व जिम्मेदारों की कार्य कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगता आया है। कुछ वर्षों पूर्व तत्कालीन कलेक्टर चंद्रशेखर बोरकर ने बस स्टेंड की व्यवस्था को चॉक-चौबंद किया था। जिससे व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ था, लेकिन उनके जानके बाद स्थितियां बिगड़ती चली गई। देखते ही देखते बस स्टेंड की यह हालत हो गई कि बस कहां खड़ी रहेगी, ऑटो कहां खड़े रहेंगे, बाकी अन्य वाहन कहां खड़े रहेंगे, इसका किसी को कुछ पता नहीं। बस आईये और घुस जाईये बस स्टेंड में और लगा दिजिए बस स्टेंड की व्यवस्थाओं को बट्टा। कहने को यहां यातायात अमले ने जवान भी तैनात कर रखा है, मगर बस चालकों, ऑटो चालकों व अन्य वाहनों पर सिर्फएक जवान के बस मे नहीं है। स्थिति यह हो जाती है कि कई बार व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यातायात के जवान को वाहन चालकों के हाथ तक जोडने़ पड़ जाते है।

वहीं बस स्टेंड पर लगने वाले फ्रूट व चाय के ठेले भी बस स्टेंड की इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। ठेले लग जाने से बस स्टेंड का काफी हिस्सा अनुपयोगी हो जाता है। जिसके चलते भी यहां यातायात बाधित होता है। कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आपातकाल सेवाओं के लिए भी यहां रास्ता मिल पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिम्मेदारों को चाहिए कि बस स्टेंड की अव्यवस्था को व्यवस्था में तब्दील कर आमजनता व मुसाफिरों को राहत पहुंचाए।

ग्राम पंचायत सचिव हुआ निलंबित

माही की गूंज, बड़वानी। जिला पंचायत सीओ ऋतुराजसिंह ने ग्राम पंचायत निवाली बुजुर्ग के सचिव कबासिंग सेनानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सचिव कबासिंग सेनानी का मुख्यालय जनपद पंचायत निवाली नियत किया गया है। ग्राम पंचायत निवाली बुजुर्ग में दो सीसी रोड़ निर्माण के लिए निकाली गई राशि से हुए कार्य की जांच करवाने पर संबंधित पर 2 लाख 63 हजार 395 रुपए की राशि की वसूली प्रतिवेदित की गई थी। मूल्यांकन से अधिक राशि आहरित करने पर दोषी सचिव पर उक्त कार्रवाई की गई है।

कोरोना से ग्रसितों को किया पोषण किट का वितरण

माही की गूंज, बड़वानी। ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन एवं चेतना संस्था द्वारा पोषण समृद्ध ग्राम परियोजना के तहत आजीविका भवन राजपुर में डब्ल्यूएचएच प्रोजेक्ट के सहयोग से कोरोना महामारी से ग्रसित परिवार के बच्चों या सदस्यो को पोषण किट के वितरण का शुभारम्भ किया गया। ग्राम स्तर पर एक हजार 400 जरूरतमंद परिवारों को पोषण किट का वितरण किया जाएगा । इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग से निरंजन ने पोषण के महत्व पर विस्तार से चर्चा की।

महाविद्यालय में एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम

माही की गूंज,थांदला।

जागरूकता ही एकमात्र ऐसा पहलू है जो किसी भी समस्या, रोग आदि से बचाव में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण उपाय हैं। एड्स एक संक्रामक रोग है, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में असुरक्षित यौन संबंध, रक्तदान या रक्त के माध्यम से संक्रमित सुई या संक्रमित शैविंग उपकरण के माध्यम से फैलता है। इसके मुख्य लक्षणों में वजन कम, रात में पसीना आना, कमजोरी है। रोग प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाने से अन्य रोगो से ग्रसित हो जाते है। यह रोग लाइलालज है, जागरूकता व सावधानी ही इसका एक मात्र उपचार है।

प्रत्येक विद्यार्थी अपने गांव का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय से प्राप्त जानकारी अपने तक सीमित न रखकर अपने गांव में एड्स के प्रति जागरूक कर इस लाइलाज रोग से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

उपरोक्त जानकारी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत रेडरिबन क्लब द्वारा विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. राठौर एवं विशेष अतिथि डॉ. अवास्या तथा महाविद्यालय के प्राचार्य, डॉ.जी.सी. मेहता ने संबोधित करते हुए बताया। साथ ही डॉ. पीटर डोडियार, प्रो. एस.एस. मुवेल, प्रो. एजाज हुसैन, प्रो. छतरसिंह चौहान, ने भी एड्स संबंधी जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉ. मीना मावी, डॉ. शुभदा भोसले, डॉ. दीपिका जोशी, प्रो. महेश कुमार तिवारी, प्रो. कंचना बारस्कर सहित बडी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ प्रभारी प्रो. एच.डुडवे ने एवं आभार राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संयोजक डॉ. बी.एल. डावर ने माना।

पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बड़वानी में मनाया विश्व एड्स दिवस

माही की गूंज, बड़वानी। पॉलीटेक्निक महाविद्यालय बड़वानी के प्राचार्य उत्कर्ष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तथा प्रभारी विभागध्यक्ष टीएल ठाकुर के मार्गदर्शन में रेड रिबन क्लब के अन्तर्गत विश्व एड्स दिवस मनाया गया। जिसमें जिला चिकित्सालय बड़वानी से पधारे मुख्य अतिथि डॉ. लक्ष्मी माहौर जिला महामारी विशेषज्ञ द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर छात्रों एवं स्टाफ की उपस्थिति में एड्स से सुरक्षा तथा बचाव के बारे में व्याख्यान दिया। इसी कड़ी में डॉ. माहौर द्वारा वर्तमान में चल रहे कोविड-19 से बचने के उपायों के बारे में भी जानकारी देकर सभी से कोविड टिकाकरण कराने का आग्रह किया। छात्र-छात्राओं ने डॉ. माहौर से एड्स से संबंधित बीमारी के बारे में प्रश्न पूछे जिनका बहुत ही सरलता से छात्रों के प्रश्नों का जवाब दिया। संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम सहायक श्री संजय परमार ने किया। इस अवसर पर संस्था के छात्र-छात्राओं के साथ नवल भोसले, महेन्द्र बरडे, अमरसिंह चैहान, मोहन डावर, दिनेश डावर, श्रीमती निमिया सोलकी श्रीमती भूमिका पाटीदार, शीतल पाटीदार, श्याम द्विवेदी, अनुराग जोशी, सचिन शर्मा उपस्थित थे।

स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान कम नही है- केबिनेट मंत्री पटेल

माही की गूंज, बड़वानी।

स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश के जनजातीय नायकों का भी योगदान कम नही है। कई जनजातीय नायकों ने अंग्रेजों के दमन का मुकाबला डटकर करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। किन्तु अभी तक इनकी गाथाओं को उचित स्थान नही मिला था। जिसके कारण यह लोकोक्तियों और जनजातीय समाज के परंपरागत गीतों, संदेशों में ही दर्ज थे। अब प्रदेश की सरकार ने इन जनजातीय बंधुओं की शहादत को भी आमजनों तक पहुंचाने का जो प्रयास प्रारंभ किया है। वह काबिल-ए-तारिफ है। और हमारा जनजातीय समाज सरकार के इस प्रयास की पूरजोर सराहना करता है। 1857 की क्रांति से अभी तक जनजातीय भाइयों ने जो राष्ट्र और संस्कृति को बचाने का कार्य किया है उसे प्रदेश की सरकार ने याद किया है।

प्रदेश के पशुपालन एवं सामाजिक कल्याण मंत्री तथा बड़वानी के विधायक प्रेमसिंह पटेल ने जिले में आई क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा के दौरान बड़वानी में आयोजित सभा के दौरान कही। इस दौरान कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने दो दिवसीय यात्रा के दौरान दिये गये सहयोग के लिए जनप्रतिनिधियों, रहवासियों, कर्मचारियों-अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए यात्रा को ऐतिहासिक बताया। वही भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी एवं दीपक शर्मा ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना करते हुए इसे जनजातीय बंधुओं का मान बढ़ाने वाला बताया।

शहीद भीमा नायक महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान आदिवासी लोकगीतों के गायक आनंदीलाल भावेल के गीत पर उपस्थित अतिथियों, जनप्रतिनिधियों एवं रहवासियों ने भी जमकर नृत्य कर, अपनी खुशी का इजहार किया।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्री पटेल, कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी, टंट्या मामा के वंशज, पलसूद नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रमा वास्कले सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, युवा उपस्थित थे।

रिमझिम पानी से और बढ़ गया जनजातीय बन्धुओं का उत्साह

मंगलवार को जिले में ग्राम बोबलवाड़ी से प्रवेश करने वाली क्रांति सूर्य गौरव यात्रा दूसरे दिन बुधवार को निवाली से प्रारंभ होकर बड़वानी होते हुये धार जिले के कुक्षी के लिये प्रस्थान हुई। दूसरे दिन क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का स्वागत इन्द्र देवता ने भी रिमझिम बारिश के साथ किया। बरसते हुये पानी के साथ जिले के जनजातीय बन्धुओं एवं अन्य रहवासियों का उत्साह बढ़ता ही गया, सम्पूर्ण यात्रा मार्ग में कलश का स्वागत जगह-जगह ग्रामवासियों ने सड़के दोनो किनारो पर खड़े होकर पुष्प वर्षा के साथ किया। वहीं महिलाओं ने कलश यात्रा का स्वागत सर पर कलश धारण कर किया । प्रदेश के केबिनेट मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने भी क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का स्वागत ग्राम धाबाबावड़ी में बने शहीद भीमा नायक स्मारक पर पहुंचकर किया ।

कलेक्टर ने किया जिला चिकित्सालय के आक्सीजन संयंत्र का निरीक्षण

माही की गूंज, बड़वानी।

कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जिला चिकित्सालय के पदाधिकारियों के साथ जिला चिकित्सालय में नव निर्मित आक्सीजन संयंत्र का निरीक्षण किया एवं उसकी कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होने निर्देशित किया कि, कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर आक्सीजन संयंत्र को 24 घंटे क्रियाशील बनाये रखा जाये। जिससे आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके।

इस दौरान कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय में बन रही पीआईसीयू का भी निरीक्षण कर इसका निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस दौरान कलेक्टर ने सोनोग्राफी लैब का भी निरीक्षण कर निर्देशित किया कि निर्धारित मानको अनुसार आने वाले सभी लोगों की सोनोग्राफी हो यह सुनिश्चित किया जाये। अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान कलेक्टर ने कोविड आईसीयू एवं ट्रामा सेंटर में बनाये गये वार्ड का भी निरीक्षण कर, अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद सत्य को हिदायत दी कि, उक्त व्यवस्था इस प्रकार तैयार रखी जाये कि जैसे ही आवश्यकता पड़े इसका उपयोग रोगियों के हितार्थ किया जा सके। ज्ञातव्य है कि, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान ने वीडियों कांफ्रेंसिंग के दौरान प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया था कि, वे जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि नव निर्मित आक्सीजन संयंत्र सुचारू रूप से कार्यरत है। एवं कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जिला चिकित्सालय में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है।

जीप में भारी लगेज के साथ सवारियां भर बनाया ट्रक

जान जोखिम में डाल रहे वाहन चालक, प्रशासन आंखे मूंदे बैठा

माही की गूंज, आम्बुआ।

चार पहिया वाहन वह भी जीप जैसा वाहन पहले कमांडर जीप जिसमें यात्री वाहन की तरह सवारियां ढोई जाती रही और अब तूफान जीप जो कि तूफान की गति से सवारिया ही नहीं अपितु लगेज भी इतना कि देखने वाले अचंभित होकर दांतो तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाए। ये यमदूत के शक्ल में सरपट दौड़ते वाहन क्या प्रशासन की नजरों में नहीं आते...?

यात्री बसें चलाने हेतु परमिट, फिटनेस, सर्टिफिकेट, चालक, परिचालक हेतु लाइसेंस तथा यूनिफॉर्म लेकिन जीपो तथा ऑटो रिक्शा, मैजिक आदि के लिए यह सब नहीं चाहिए होता है। तभी तो यह वाहन बे-रोक टोक सड़कों पर फर्राटे भरते हुए पुलिस चौकियों, थानों तथा यातायात विभाग के दफ्तरों के सामने से कर्कश हांर्न और कभी-कभी सायरन जैसी आवाज निकालते हुए निकल जाते हैं और कोई कार्रवाई होती हो तो पता नहीं।

कुछ वर्षों पूर्व कमांडर नाम की जीप हालांकि अभी भी कुछ स्थानों पर दौड़ रही है, जिसमे 70 से 80 सवारियां अंदर और बाहर के साथ ही बोनट पर सवारियों के साथ लगेज रखकर ड्राइवर एक तरफ आधा लटका हुआ सैकड़ों जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता देखा जाता रहा, और अभी देखा जा सकता है।

अब कमांडर का जमाना कुछ कम हुआ और सड़कों पर तूफान नाम की जीप तूफान मचाने आई। जैसा नाम वैसा काम भी वाहन की चाल तूफानी के साथ-साथ अंदर बेहिसाब सवारिया तथा छत पर इतना सारा लगेज कि किसी छोटे ट्रक या बस की छत भी छोटी पड़ जाए।

सामान के साथ दो पहिया वाहन साइकल नहीं मोटरसाइकिल एक नहीं दो-दो या तीन-तीन सामान के साथ बंधी देखी जा सकती है। यह नजारा तब देखने को मिलता है जब मजदूर या तो गुजरात जाते हैं या वहां से वापस अपने घरों को आते हैं। ऐसे यमदूत के समान चलने वाले ये वाहन यात्रा कर रहे यात्रियों ही नहीं अपितु सड़क पर पैदल, दो पहिया या चार पहिया वाहनों वाले यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। कई ऐसी जीपें जिनके नंबर प्लेट पर पूरे नंबर नहीं है, वह भी सवारिया ढोकर दौड़ती है। यदि यह दुर्घटना कर भाग जाए तो इन्हें किस आधार पर पकड़ा जा सकता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि, यह यमराज के वाहन क्या किसी थाने पुलिस चौकी और यातायात थाना तथा आरटीओ कार्यालय के सामने से नहीं गुजरते होंगे...? सड़क पर सरपट दौड़ते समय क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं पड़ती होगी...? तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं होती...? क्यों लोगों की जिंदगी से खेलने की छूट इन्हें दी जा रही है...? इन वाहनों के चालकों के चालकों में कई बगैर लाइसेंस तो होते ही हैं वाहनों के कागजात भी पूरे होंगे यह भी कहा नहीं जा सकता। साथ ही कई चालक अव्यस्क भी देखे जा सकते हैं जो कि सवारियां भरकर सड़क पर वाहन चलाते हैं। यह वाहन यात्री बसों के आगे-आगे सवारियां भरते जाते हैं तथा यात्री वाहन चालक परिचालको से जब तक तू-तू, मैं-मैं करते रहते हैं। क्योंकि यह वाहन उनके होते हैं जो इन क्षेत्रों में रहते हैं जहां से बसें भी गुजरती है इनसे बस मालिक तथा चालक परिचालक परेशान होते रहते हैं।

पंचायत चुनाव की सुरसुरी से भावी प्रत्याशी हुए चौकन्ने

परिसीमन से बनी नई पंचायतें समाप्त हो जाने से मायूसी

माही की गूंज, आम्बुआ। जगराम विश्वकर्मा

विगत वर्ष समाप्त हुए पंचायत के कार्यकाल को बार-बार बढ़ाए जाने से जहां पुराने सरपंच चुनाव से बचकर खुश थे, वहीं चुनाव का इंतजार कर रहे विरोधी मन मसोसकर रह रहे थे। परिसीमन के बाद नई पंचायतें बनने से खुश हो रहे ग्रामीण तथा भावी उम्मीदवार अब मायूस नजर आ रहे हैं।

जैसा की विदित है, ग्राम पंचायत के चुनाव वर्ष 2014 में संपन्न हुए थे तथा उनका 5 वर्ष का कार्यकाल 2019 में समाप्त हो रहा था। इसी बीच प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी चुनाव की बजाए पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाते हुए सरपंचों को सभापति घोषित कर दिया। इसके बाद कोरोना की दस्तक यानी की महामारी ने चुनाव पर पानी फेर दिया। पुराने सरपंच बगैर चुनाव के ही पहले की भांति कुर्सी पर चिपक गए और चुनाव का रास्ता देख रहे विरोधी जो कि भावी उम्मीदवार का सपना संजो कर बैठे थे बैठे ही रह गए। विगत दिनों विधानसभा उप चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत चुनाव की उम्मीद जागी तो चुनाव लड़ने की राह देख रहे भावी उम्मीदवारों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई देने लगी है। इसके बाद एक बार फिर चुनाव टलते नजर आए और अब वर्तमान सरकार यानी कि शिवराज सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के समय किए पंचायतों के परिसीमन जिसके कारण वे पंचायतें जिसमें एक से अधिक गांव सम्मिलित थे, उन पंचायतों का विभाजन होकर नई पंचायतों की घोषणा होने से ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त था। उन्हें लग रहा था कि, अलग-अलग पंचायतें होने से अब उनके ग्राम विकास के सपने साकार होंगे। क्योंकि उन्हें उनकी पंचायतों का बजट मिलेगा जो कि, पूरा का पूरा उन्हीं के ग्राम विकास पर खर्च होगा। मगर जैसे ही परिसीमन समाप्ती की घोषणा हुई वह भी मायूस हो गए, उन्हें पुनः पूर्व पंचायतों के अधीन रहना पड़ेगा। स्मरण रहे कि, एक पंचायत जिसमें अन्य ग्राम शामिल होते और जिस ग्राम का सरपंच होता है वह कितनी भी इमानदारी से कार्य करें फिर भी वह उस ग्राम को अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करता है करता दिखता है जिस ग्राम का वह निवासी होता है। संलग्न ग्रामों पर कम ध्यान देने का आरोप उस पर लगता ही है। इसलिए वे गांव अपनी अलग पंचायत चाहते हैं ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने ग्राम का विकास करा सके। अब जबकि पंचायत चुनाव की तैयारियों की सरगर्मी बढ़ती लग रही है तब भावी प्रत्याशियों के चौकन्ने होने का समय है और वे सक्रिय होने लगे हैं। मतदाताओं की पूछ परख पुनः बढ़ती नजर आने लगी है। इंतजार है तो बस चुनाव की घोषणा का, वह चुनाव आयोग कब करता है या फिर पुनः किसी कानूनी दांवपेच में उलझ कर वर्तमान सरपंच को और अधिक दिनों तक कुर्सी पर बैठने का मौका दिया जाएगा।

रोको-टोको अभियान के तहत आमजन को दी समझाईश

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प के दिशा निर्देशानुसार पर जिले में कोविड-19 से बचाव हेतु रोको-टोको अभियान अंतगर्त आमजन को जागरूक किया जा रहा है। रोको-टोको अभियान के तहत वाहन चालकों, आमजन एवं दुकानदारों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेन्सींग का पालन करने तथा हाथों को सेनेटाईज करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रोको-टोको अभियान के तहत जिलेवासियों को कोरोना से बचाव हेतु सावधान रहने के लिए जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

सोंडवा में रोको-टोको अभियान के तहत आमजन, राहगीरों, दुकानदारों को कोविड-19 से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने हेतु जागरूक किया गया।

कलेक्टर श्री पुष्प ने जारी किए निर्देश

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए कि, कोविड-19 से बचाव हेतु जिले के समस्त नगरीय, कस्बाई एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोको-टोको अभियान प्रभावी ढंग से संचालित करते हुए जिलेवासियों को कोविड-19 से बचाव हेतु विशेष सावधानी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। रोको-टोको अभियान के तहत आमजन को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के पालन हेतु जागरूक करें। साथ ही कोविड-19 से बचाव हेतु टीकाकरण के दोनो डोज लगाने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करें। उक्त कार्य में राजस्व, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग सहित अन्य विभाग मिलकर समन्वित प्रयास करते हुए आमजन को कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूक करने के प्रयास करें।

कोविड संक्रमण से मृत हुए व्यक्तियों की अनुग्रह राशि के 18 प्रकरण स्वीकृत

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर म.प्र. शासन द्वारा जारी अनुग्रह राशी प्रदाय किए जाने के दिशा निर्देश के परिपालन में कलेक्टर मनोज पुष्प के मार्गदर्शन में प्रकरण समीक्षा समिति द्वारा प्राप्त 18 आवेदनों को स्वीकृत प्रदान करते हुए प्रति प्रकरण अनुसार 50-50 हजार रूपए की अनुग्रह राशी स्वीकृत के आदेश जारी किए गए है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि, 18 प्रकरण स्वीकृत किए गए है। स्वीकृत प्रकरण में मृतक के वारिसान शंकुन्तला भट्ट पति स्व. रजनीकांत भट्ट निवासी अलीराजपुर, महेश चन्द्र गेहलाद पत्रि स्व. चन्द्रकला गेहलोद निवासी अलीराजपुर, रामदेवी वर्मा पति रामबाबु वर्मा निवासी सिलोटा सोंडवा, लक्ष्मणसिंह चौहान पत्रि स्व. रमेश चौहान निवासी अलीराजपुर, निलोफर शेख पति स्व. मोहम्मद शेख निवासी चन्द्रोखर आजाद नगर संतोषी भूरिया पति स्व. केनथ भूरिया निवासी जोबट, सविता निगम पति स्व.निगम रेंमंडसिंह निवासी जोबट, अलका वाणी स्व.उमेश चन्द्र वाणी निवासी नानपुर, उर्मिला वाणी स्व. जगदीश वाणी निवासी नानपुर, विभा पति स्व.अंतिम चौहान निवासी अलीराजपुर, अनिल वाघेला पत्रि स्व. नीता वाघेला निवासी मालवई, राजेश गुप्ता पिता हरीश गुप्ता निवासी अलीराजपुर, राजाराम जाटव मृतक पुत्र दूर्गा राजाराम जाटव निवासी सोंडवा, जगदीप वाणी मृतक स्व. नरेन्द्र रामचन्द्र वाणी निवासी जोबट, शिव सोलंकी मृतका शर्मिला दिनो सोलंकी निवासी अलीराजपुर, किरण वाणी मृतक धनराज वाणी निवासी नानुपर, जगदीश चौहान संन्तु चौहान निवासी खुटाजा जोबट, रसीदा मकरानी स्व.अलाउद्दीन मकरानी निवासी ग्राम सन्दा चन्द्रोखर आजाद नगर को 50-50 हजार रूपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई।

उल्लेखनीय है कि, जिले में अब तक कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने के 29 प्रकरणों में 50-50 हजार रूपए की अनुग्रह राशि जारी की जा चुकी है।

मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट मे डॉ. शेख जिलाध्यक्ष नियुक्त

माही की गूंज, अलीराजपुर। देशभर में मुस्लिम मनिहार समाज के वेलफेयर के लिए कार्य कर रही सामाजिक संस्था मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर शकील अहमद को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर पत्रकार नावेद रजा ने जानकारी देते हुए बताया कि, मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट म.प्र. कोर कमेटी की सहमति से संगठन के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर रियाजउद्दीन मनिहार ने डॉक्टर शकील अहमद अलीराजपुर जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। डॉक्टर शकील अहमद की नियुक्ति पर जिलेभर के मनिहार समाजजनों में खुशी का माहौल है। ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता खालिद मनिहार, प्रदेश महासचिव तारीक मनिहार, सैयद मोहसिन बाबा, प्रदेश सचिव सद्दाम मनिहार, धार जिलाध्यक्ष साजिद मनिहार, खरगोन जिला प्रवक्ता करीम मनिहार, धार जिला उपाध्यक्ष जुनैद मनिहार, हाजी अस्दुल्लाह मनिहार, शाहरुख मनिहार सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारियों एवं मनिहार समाजजनों ने डॉक्टर शकील को बधाई प्रेषित की।

11 दिसम्बर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर। बैंक, विद्युत विभाग, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि के वसूली वाले प्रकरणों को प्रीलिटिगेशन के रूप में निराकरण हेतु 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर बकायादार को प्रावधानित छूट प्रदान की जाएगी, जिसका लाभ भी बडी संख्या में नागरिकों द्वारा उठाया जा सकता है। गौरतलब है कि, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर अरूण कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में जिला अलीराजपुर एवं तहसील जोबट के समस्त न्यायालयों में 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुघर्टना, दावा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अन्तगर्त चेक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय तथा प्रीलिटिगेशन के अंतगर्त बैंक व अन्य ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत नगर पालिका के वसूली प्रकरणों व निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अन्तगर्त चेक बाउन्स प्रीलिटिगेशन प्रकरण आदि का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों जैसे नगर पालिका, विद्युत विभाग, बीमा कंपनियां, सभी बैंक संस्थान, प्रशासकीय विभाग, अभिभाशक संघ आदि के साथ प्री. सिटिंग बैठकें की जा रही है। यूनियन बैंकए बैंक ऑफ़इण्डिया म.प्र. ग्रामीण बैंक आदि के अधिकारियों तथा नेशनल इंयोरेंस कंपनी व न्यू इंडिया इंयोरेंस कपंनी के अधिकारियों द्वारा बैठक में प्रकरणों पर चर्चा की गई।

बार-बार बिजली केबल हो रही फाल्ट, घटिया केबल से जनता हो रही त्रस्त

वोल्टेज समस्या के कारण जल प्रदाय में आती है परेशानी

माही की गूंज, आम्बुआ।

आम्बुआ कस्बे में लगभग 4 वर्ष पूर्व बिजली के तार निकालकर विद्युत विभाग ने ठेकेदार के माध्यम से जो केबल लाइन डाली थी उस समय इसका विरोध हुआ था मगर ध्यान नहीं दिया गया और जिसका खामियाजा जनता के साथ-साथ बिजली कर्मचारी आज तक उठाते आ रहे हैं। केबल कभी भी जलकर फाल्ट हो जाती है। ठेकेदार अपना कार्य कर चला गया अब जनता हो रही परेशान।

जैसा की विदित है, बिजली तारों से सीधे कनेक्शन लेकर बिजली चोरी रोकने हेतु शासन तथा विद्युत विभाग ने लोहे तथा एल्युमिनियम के तारों को निकाल कर आम्बुआ कस्बे में माह अगस्त-सितंबर 2017 में केबल का जाल बिछाया था। जिस समय केबल बिछाई जा रही थी तभी क्षेत्र के लोगों तथा पत्रकारों ने केबल के घटिया होने के कारण विरोध किया था। समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ सचित्र समाचार प्रकाशित किए गए मगर फिर भी न तो बिजली विभाग ने ध्यान दिया न ही किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया और ठेकेदार अपनी मनमर्जी दिखा कर चला गया। वर्ष 2017 से लेकर वर्तमान तक इस घटिया केबल के कारण क्षेत्र में उपभोक्ता व बिजली कर्मचारी परेशान हो रहे हैं इसके कारण वोल्टेज की कमी के चलते पेय जल योजना, आटा चक्की तथा शीतल पेय आदि के व्यवसाई परेशान है। यह केबल कब जल जाए फाल्ट होकर जमीन पर आ गिरे या कहीं भी टूट कर अधर में झूल जाए कहा नहीं जा सकता। नागरिकों की मांग है कि, कोई मजबूत केबल डाली जाए या फिर पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए।

आम्बुआ सरपंच श्रीमती वर्षा जुवानसिंह रावत ने बताया कि, बार-बार लाइन फाल्ट होने तथा वोल्टेज कम मिलने से जल प्रदाय में परेशानी आ रही है।

वही आटा चक्की व्यवसाई हर्ष खंडेलवाल ने बताया कि, कभी भी लाइन की केबल जल जाती है और घंटों लाइट बंद रहने के कारण आटा चक्की बंद रहने से परेशानी होती है।

कोल्ड ड्रिंक व्यवसाई विपिन राठौड़ ने बताया, बार-बार बिजली जाने के कारण तथा केबल फाल्ट होने के कारण हमारा धंधा प्रभावित होकर भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

फोटो कॉपी तथा ऑनलाइन व्यावसाई हुसैन नजमी ने बताया, कभी भी बिजली की केबल जल जाती है कभी खंभों पर तो कभी डीपी पर आग लग जाती है जिससे बिजली प्रदाय बंद हो जाता है तथा घंटो बंद रहती है धंधे चौपट हो रहे हैं।

वही जब उक्त मामले में बिजली अधिकारी अलीराजपुर राहुल चौहान से चर्चा की तो उनका कहना है, नगर में लोड बढ़ने से केबल फॉल्ट हो रही है। हो सकता है कि पुरानी केबल में फाल्ट हो रहा है उसे बदलने का कार्य कराएंगे।

और अब विधायक प्रतिनिधि बनने की जुगत में लगे कई कार्यकर्ता

माही की गूंज, आम्बुआ।

विगत दिनों विधानसभा क्षेत्र जोबट के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें जो हारे वे हार के कारणों की समीक्षा में जुटे हैं उनके कार्यकर्ता अपनी सफाई देते देखे जा सकते हैं ताकि अपने नेता का विश्वास कायम रख सके। मगर जो जीता है उस प्रत्याशी के नए व पुराने दोनों कार्यकर्ता संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रतिनिधि बनने की जुगत में जुटे हैं ताकि प्रशासन पर अपनी पकड़ बना सकें।

जोबट विधानसभा क्षेत्र जो कि कांग्रेस विधायक सुश्री कलावती भूरिया के निधन से खाली हुआ था पर घमासान रूप में चुनाव संपन्न हुआ। हारने तथा जीतने वालों ने अथक प्रयास किए और जीत 6 उम्मीदवारों में से किसी एक की होना थी सो हो गई। भाजपा सत्ताधारी पार्टी में झाबुआ-अलीराजपुर विधानसभा जहां सभी सीटें कांग्रेस की थी जिसमे से अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा सीट कांग्रेस से छीन कर उसकी प्रत्याशी श्रीमती सुलोचना रावत (पूर्व कांग्रेसी विधायक तथा राज्य मंत्री) जो कि, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आते ही टिकट मिला तथा जीत भी मिली। जो कार्यकर्ता कांग्रेस से उनके साथ भाजपा में आए हैं तथा वे कार्यकर्ता जो भाजपा में जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे, अब उनमें से कई कार्यकर्ता विधायक प्रतिनिधि बनने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाने में जुटे हैं।

नाम नहीं बताने की शर्त पर ऐसे ही कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि, वह इस दौड़ में सबसे आगे है। बता दें कि, विधायक प्रतिनिधि नाम की उपाधि जिन कार्यकर्ता को मिलती है वह विधायक की अनुपस्थिति में शासकीय बैठकों, भूमि पूजन, उद्घाटन, जैसे कार्यों को भी अंजाम देते रहे हैं। प्रशासनिक हम हल्कों में उनकी अपनी एक धमक होती है। यदि चार पहिया या दो पहिया वाहन हो तो उस पर विधायक प्रतिनिधि की स्वर्ण रंग की चमचमाती प्लेट जरूर लगती है और यदि वाहन नहीं होता है तो कुछ महीनों बाद वाहन की व्यवस्था, या यों कहे कि वाहन क्रय करने की क्षमता या बैंक से ऋण प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है।

विधायक प्रतिनिधि विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक स्तर पर बनाए जाते हैं पंचायत स्तर पर सरपंच प्रतिनिधि, जनपद, जिला पंचायत, कृषि उपज मंडी, सहकारी संस्थाओं आदि अनेक विभाग है जिनमें अलग-अलग विधायक प्रतिनिधि नियुक्त कर कार्यकर्ताओं को खुश कर दिया जाता है या तो कहे की प्रतिनिधि रूपी झुनझुना थमा कर कार्यकर्ताओं को कार्य का तोहफा दिया जाता है। अभी नियुक्तियां नहीं की गई है मगर ऐसे पद चाहने वाले जीतोड़ जुगाड़ में जरूर रहे हैं। देखें किसे क्या मिलता है कौन खुश होता है और कौन मायूस होता है।

आठ दिन पहले मिल चुकी बायोडीजल की एनओसी तो क्यों छापा समाचार...

मुंह मांगी मांग भर और प्रशासन के आला अधिकारियों के मुंह में चांदी की चम्मच ठूंसकर विधी विरूद्ध हर कार्य कर दिया जाता है, का खुद अधिकारी दे रहे प्रमाण

माही की गूंज, टीम के साथ संजय भटेवरा की रिपोर्ट

झाबुआ। जिले में अवैध रूप से बायोडीजल प्रशासनिक आला अधिकारियों की मुंह मांगी मांग का सिंदूर भरकर मुंह में चांदी की चम्मच ठुसकर खुल्लेआम बायोडीजल के नाम पर केमिकल युक्त नकली डीजल रामपाल से लेकर युसूफ, युसूफ से लेकर अज्जू-विज्जु और अज्जू-विज्जु से लेकर अंतरवेलीया का जयदीप बायो फ्यूल आदि सभी स्थानों पर लगे पंप व टैंकरों से सीधे खुले में मशीन लगाकर ढाबा संचालको का संरक्षण लेकर किस तरह से खुल्ले रूप से बायोडीजल के नाम पर केमिकल युक्त नकली डीजल का कारोबार चल रहा था और अधिकारी के मुंह में चांदी की चम्मच ठुसकर उनकी मुंह मांगी मांग भर देने के कारण प्रशासनिक कार्रवाई किस तरह की इन माफियाओं के विरुद्ध रही। पूरी बैबाकी व हमारी लेखनी के साथ माही की गूंज ने खुलासा किया। आगे भी इस अवैध कारोबार पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन हमारे समाचारों से माफिया से लेकर जिला प्रशासन तक ऐसे हरकत में आए कि, मानो इनका बस चले तो हमारा मर्डर भी करवा दे। चांदी की चम्मच ठुसवाने वाले अधिकारियों ने इन्हीं माफियाओं को सलाह देकर हमें दबाने व धमकाने में भी किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी।

नतीजन जिले में किसी को भी नहीं पहचानने का दावा करने वाला समाजसेवी का चोला ओढ़ झाबुआ से लेकर भोपाली भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त कर रामपाल उर्फ सोनु चौहान उफ बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल का माफिया ने गूंज टीम के सदस्य को कवरेज करते समय छापरी स्थित अवैध पंप का कवरेज करने पर माफिया रामपाल ने गुर्गों को आदेश कर घेर लिया और मोबाइल-कैमरा छीन लिया तथा ऑफिस में बुलाकर जातिवाद व भ्रम फैलाकर दबाने का प्रयास किया। पर माही की गूंज टीम ने अपने कर्तव्यत्ता का परिपालन कर रामपाल के सफेदपोश के पीछे छुपे माफिया रूपी चेहरे को उजागर किया। जिसके बाद बात करने के नाम पर झाबुआ के माही की गूंज कार्यालय पर आया और अपने आप को जनजाति का नेता बताकर समाज व संगठन के नाम पर धमकाने का असफल प्रयास करते हुए कहा, हम आदिवासी हैं और तुम महज आदिवासी का विरोध करते हैं, इसलिए हमें आगे नहीं आने देना चाहते हो और इसी नियत से समाचारों का प्रकाशन कर रहे हो। रामपाल ने समाज व संगठन का चोला ओढ़ हर तरीके से दबाने का प्रयास किया। जब हमने हमारी चुप्पी तोड़ कहां कि, असल में आदिवासी का शोषण कौन कर रहा है...? आपके गांव में एक समग्र आईडी में नाम जोड़ने के लिए सरपंच-सचिव दो सौ से पांच सौ रुपए ले रहे है जिसके लिए आपने क्या कदम उठाए...? हम पत्रकार ही है जो अंतिम छोर के व्यक्ति की समस्या को जातिवाद से उपर उठकर हर समाज वर्ग के हित में उजागर कर शासन-प्रशासन के सामने लाते हैं। आप अपने माफियाई राज को प्रबल करने के लिए जातिवाद का बीज क्यों बोते हो...? माफियाओं की कोई जात नहीं होती कहां...!

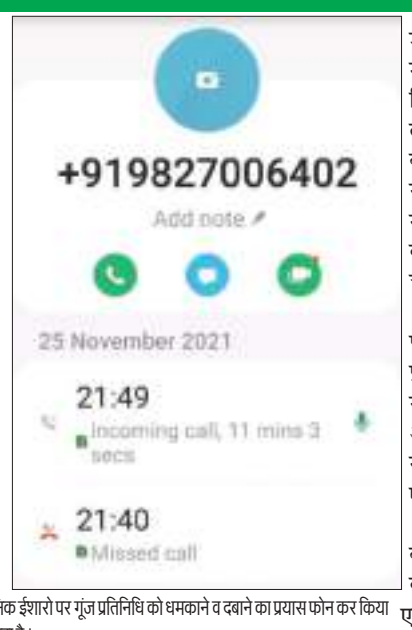

गूंज समाचारो से डीजल माफियाओ मे ऐसी हडकंप मची हुई है कि प्रशासनिक ईशारो पर गूंज प्रतिनिधि को धमकाने व दबाने का प्रयास फोन कर किया जा रहा है।

इतना ही नहीं रामपाल के जातिवाद के साथ धमकाने पर सीधे से जब पूछा, तुम कौन से गांव रहते हो...? रामपाल ने बताया, कल्याणपुरा के संदला। हमने ''जाको राखे साईयां, मार सके ना कोई'' के स्लोगन को आत्मसात कर रामपाल को कहा तुम्हारे हाथ से अगर हमारी मौत लिखी है तो हमें मरना मंजूर है, तेरे गांव में चाहे जिसको फोन कर दे मैं अकेला जाता हूं, तुझे मेरा मर्डर करवाना हो तो करवा दे। परंतु तेरे जैसे माफिया से डर कर हमारी कलम नहीं रूक सकती, हम ने जवाब दिया।

जिसके बाद रामपाल को लगा कि, उसकी जातिवाद की कूटनीति यहां काम नहीं करेगी। जिसके बाद माफिया रामपाल उसके द्वारा कहे शब्द पर माफी मांग कर रवाना हुआ।

"सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली" उर्फ जयदीप बायो फ्यूल

बायोडीजल के अन्य समाचारों के साथ हमारे पिछले अंक 25 नवंबर को प्रकाशित समाचार ''माफिया के दो आगे माफिया, माफिया के दो पीछे माफिया, बोलो कितने माफिया...?'' शीर्षक के साथ प्रकाशित किया था।

समाचारों से सभी डीजल माफियाओं में हड़कंप मची हुई है, यह तय है। इतना ही नहीं हमें कई तरह से धमकाने व दबाने का असफल प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंतरवेलिया के जयदीप बायो फ्यूल के संचालक जो कि अपने आपको भी पत्रकार बता रहा है, ने धमकाने व दबाने का प्रयास करते हुए कहा, ''तुमने किस आधार पर समाचार प्रकाशित किया और ''सौ चूहे खाकर बिल्ली हज पर चली'' की तर्ज पर पिछले पांच वर्षो से एमपीआरडीसी की बिना परमीशन व बिना कलेक्टर एनओसी के जयदिप बायो फ्यूल पंप चलाने वाला 25 नवम्बर को रात में 9827006402 से फोन कर कहने लगा आपने जयदीप बायोडीजल के नाम से न्यूज़ छापी है, न्यूज़ छापने के पहले हमसे पूछा था क्या...? हमसे जानकारी मांगों की हमारी एनओसी हुई कि नहीं, हमारे पास कागज है कि नहीं, बिना जाने कैसे न्यूज़ छाप दी...।

जिसके जवाब में हमने कहा कि माही की गूंज तथ्यात्मक रूप से समाचार प्रकाशित करता है। अगर लगता है कि, समाचार गलत है तो न्यायालय में जाए मैं वहां सारे प्रणाम प्रस्तुत करूंगा। जिसके बाद जयदीप बायो फ्यूल का संचालक कहने लगा, 8 दिन पहले कलेक्टर की एनओसी मिल चुकी है, जिले में दो एनओसी एक सांरगी (पेटलावद) के यतिन भटेवरा को प्रथम एनओसी और दूसरी एनओसी मुझे मिली है। एमपीआरडीसी की परमिशन नहीं थी और मेरा पंप 2017 से चल रहा है।

जब हमने सवाल किया कि एनओसी 8 दिन पहले कलेक्टर से मिली है तो 2017 से अब तक अवैध रूप से डीजल पंप चल रहा था...? के जवाब में संचालक कहने लगा केंद्रीय गजट में लिखा है सितंबर 2020 के पहले के लगे बायोडीजल पंप को किसी प्रकार की कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं थी। मेरे सारे कार्य एक नंबर में कर राजस्थान के शिवम एजेंसी से बायोडीजल मंगवा कर प्रतिमाह दो से चार लाख रुपए जीएसटी के भरता हूं।

जब गजट में सितंबर 2020 के पूर्व के लगे बायो पंप में अन्य किसी प्रकार की एनओसी की आवश्यकता नहीं थी तो एनओसी 8 दिन पूर्व आपको क्यों लेना पड़ी...? के जवाब में संचालक कहता है, गवर्मेंट ने कहा तो एनओसी ली गई।

जयदीप बायो फ्यूल के संचालक की गोलमोल व दवाब पुर्ण बातों के बाद जब हमने कहा कि कलेक्टर ने एनओसी जारी की है और आप एक नंबर का कार्य कर रहे हो तो हम आपके पक्ष में खड़े रहेंगे, लेकिन जो एनओसी कलेक्टर ने जारी की है वह बता दे।

जिस पर अपने आपको पत्रकार कहने वाला पंडित बौखलाने लगा और कहने लगा, मैं तुमको सिर्फ यह बता सकता हूं कि एनओसी मिल चुकी है, पर मैं तुम्हें एनओसी नहीं दिखाऊंगा, मैं पंडित हूं और मैं किसी भी अधिकारी के मुंह में चांदी की चम्मच नहीं ठुसता हूं।

इतना ही नहीं यह भी स्वीकार किया कि, जिले में दो पंप को छोड़कर सभी नकली बायोडीजल का कारोबार कर रहे हैं, यहां तक कि राणापुर पंप की भी एनओसी नहीं है। वहीं पंडित कहता है, मैंने स्वयं ने 181 पर शिकायत की है कि, जिले में अवैध रूप से बड़े रूप से अवैध बायोडीजल का कारोबार चल रहा है और गवर्मेंट का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। माही की गूंज समाचारों को पुरी प्रमाणिकता के साथ प्रकाशित करता है, यहां अवैध बायोडीजल को लेकर माही की गूंज में छपे सारे समाचारों को प्रमाणित स्वयं बायोडीजल का संचालक भी कर रहा है।

बता दें कि माही की गूंज ने 25 नवम्बर के अंक के एक कालम में जयदीप बायो फ्यूल पंप के संम्बध में प्रकाशित किया था कि, अंतरवेलिया का जयदीप बायो फ्यूल भी प्रशासन की नकली कार्रवाईयों के बाद अब यथावत अपने रंग में चल रहा है, पिछले महिनों में खबरे प्रकाशित होने के बाद अंतरवेलिया के इस जयदीप बायो फ्यूल पर प्रशासनिक अधिकारियों ने दिखावे की कार्रवाईया की। मगर पुर्ण रूप से इसे हटाया नहीं गया। इसके पिछे की काहानी बताने वाले बताते है कि, अधिकारियों के मुंह मे चांदी के चम्मच ठूस दिए गए और आला अधिकारियों की मांग पुरी कर दी गई और आगे भी इसी तरह हर महीने मांग भरने का वादा डीजल माफिया से करवा लिया गया। इसी का नतीजा है कि अंतरवेलिया का यह अवैध डीजल पंप अब भी यथावत चालु है। उक्त बात प्रकाशित होने पर हमारे सुत्र बताते है कि प्रशासन के सम्बधित आला अधिकारी भी हरकत में आये और जिस तरह से मिलजुल कर चांदी की चमम्च ठुस-ठुसवाकर पंप चालु किया गया। जिस पर अधिकारी ने पंप संचालक को दबाया और आगे से गूंज में कोई समाचार प्रकाशित न हो ऐसा प्रयास करने की बातचीत आपस में हुई। ऐसा सुत्र बता रहे है। जिसके बाद पंप संचालक पडिंत जी ने गूंज प्रतिनिधि को फोन लगाकर आगे इनकी अनियमिता का समाचार गूंज में प्रकाशित न हो इस नियत से धमकाने-दबाने व कानुन का पाठ पढ़ाने के साथ हमदर्दी जताकर समाचार रोकने का असफल प्रयास किया।

एनओसी दिखाने से आखिर क्यों किया इनकार...?

जयदीप बायो फ्यूल के संचालक बौखलाहट के साथ कह रहे हैं कि, मैं किसी भी अधिकारी के मुंह में चांदी का चम्मच नहीं ठुसता हूं, साथ ही एनओसी नहीं दिखाने की बात कर रहे हैं। दी गई एनओसी संचालक के द्वारा बिना चांदी की चम्मच अधिकारियों के मुंह में ठुसे नहीं दी गई होगी यह तय है। अगर बात माने पंडित जी की, तो उन्हें एनओसी मिल गई है तो तय है दी गई एनओसी में ऐसी भ्रांतियां होगी जो गूंज के सामने आने के बाद एनओसी जारी करने वाले संबंधित अधिकारियों से लेकर कलेक्टर तक बात आ जाए। इसीलिए एनओसी बताने से इंकार कर रहे है।

अगले अंक में हम प्रणाम के साथ यह खुलासा करेंगे कि, अधिकारियों की मुंह मांगी मांग का सिंदूर भर अधिकारियों के मुंह में चांदी के चम्मच ठुसकर किस तरह से विधी विरूद्ध हर कार्य कलेक्टर की नाक के नीचे से कर दिया जाता है। जिसका प्रणाम खुद अधिकारी दे रहे है। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन पंप की एक ही दिनांक व एक ही पत्र क्रमांक पर दो आदेश जारी किए, जिसमें एक पत्र में आपत्ती जारी की तो दूसरे पत्र में एनओसी दी गई।

मुआवजे के नाम पर किसानों का मज़ाक उड़ाती सरकार

कपास और गेहूं की फसल हुई बर्बाद 186,190, 217 रुपये के दिये किसानों को चैक

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

यहां कांडला गुजरात से गौरखपुर उत्तरप्रदेश तक अंडरग्राउंड गैस लाइन बिछाने का कार्य फूलमाल से कल्याणपुरा, देदला, मुंडट झावलिया, रल्यावन, सोयला, रताम्बा, बनी होते हुए बेकल्दा की तरफ जा रही, जिसमे क्षेत्र के किसानों कि कपास की खड़ी फसल तो रबी की गेंहू, चने का बड़ा रकबा बर्बाद हुआ। कहने को किसानों को मुआवजा भी दिया गया लेकिन वो मुआवजा न हो कर उन किसानों का मज़ाक उड़ाया गया। किसानों को ना के बराबर जमीनी मुआवजा दिया जा रहा है। और फसल नष्ट की जा रही है। यहां विकास खण्ड की ग्राम पंचायत झावलिया में मुआवजा राशि के नाम पर किसानों से लाइन बिछाने वाली एजेंसी ने सरकार के साथ मिल कर किसानों को मुआवजे के नाम पर 150 से लेकर 500 रुपये तक के चैक दिए, कुछ किसानों को जरूर 5 हजार से अधिक मिला लेकिन जितनी कृषि भूमि लाइन बिछाने में बर्बाद हो रही हैं उसके मुकाबले मिलने वाली मुआवजा राशि बेहद ही कम है।

मुआवजा राशि 186 रुपये की राशि के साथ किसान।

झावलिया क्षेत्र के किसानों विजयसिंह खराड़ी ,भूरा सिंगाड, रूपचंद सिंगाड, मांगू सिंगाड, झितरा नानूराम मुणिया, रुमाल मुणिया, भीला खराड़ी, मला खराड़ी, खुनसिंह खराड़ी, प्रभु खराड़ी, नारायण गरवाल, सनिया गरवाल, पागला मुणिया, सनिया मुणिया, सैतान मुणिया, अमरसिंग मुणिया, कालिया मुणिया, उकारी मुणिया, कालू भाभर, सामा भाभर, राधु वसुनिया आदि ने बताया कि, लाइन कम्पनी द्वारा हमारे खेत के बड़े हिस्से मे खड़ी कपास की फसल को बर्बाद किया और गेहूं की फसल भी जिस स्थान से लाइन गुजर रही है, वहा नही बोने दी, लाइन बिछाने के दौरान कम्पनी के बड़े वाहन हमारे खेतो से फसल बर्बाद कर निकल गए। कम्पनी द्वारा सरकार की अनुमति से कार्य कर मुआवजा दिए जाने की बात कही थी, लेकिन जब कम्पनी द्वारा मुआवजे की राशि के चैक दिए वो बहुत कम थे। कई किसानों को 150 से 200 रुपये दिए गए जो उचित नही है। बताया जा रहा है ग्राम पंचायत रताम्भा के कुछ किसानों ने कलेक्टर से गुहार भी लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई, किसानों ने उचित और सही मुआवजा राशि की मांग की है ,वही राजस्व विभाग के तहसीलदार जगदिश वर्मा ने कहा है कि, अगर कोई शिकायत मिलती है तो मामले को दिखा कर किसानों की सुनी जाएगी।

दो फसल हुई बर्बाद , कहा है किसान हितेषी शिवराज सरकार

गत दिनों सही मुआवजा राशि की मांग को लेकर सैकड़ो किसान माही डेम चारनपुरा में धरने पर बैठ गए थे, माही डेम के डूब क्षेत्र में आने वाले किसान आज तक विस्थापित नही हो सके वही उनकी जमीन का मुआवजा भी सही नही मिला, यहां पाइप लाइन डालने वाली कम्पनी द्वारा किसानों की दो फसल बर्बाद करने के बाद भी मामूली मुआवजा दिया गया है, हालांकि पाईप लाइन अंडरग्राउंड बिछाई जा रही है लेकिन किसानों का कहना है कि, जहा से लाइन निकली है वो भी भूमि उपयोग की नही रही वही कम्पनी द्वारा कभी कही भी रिपेयरिंग और टेस्ट के लिए लाइन खोदने का कार्य समय-समय पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार खुद को किसान हितेषी बताती है लेकिन धरातल पर कहानी कुछ और ही है। इस प्रकार के कार्यो में कम्पनी क्या और कैसे मुआवजा बाट रही है इसकी कोई जानकारी प्रशासन को नही दी जाती वही किसानों की मांग को हवा में उड़ा दिया जाता है, झावलिया पंचायत के किसानों ने कहा है वो मामले में तहसीलदार को शिकायत करेगे वही विधायक प्रतिनिधि जीवन ठाकुर ने कहा कि, वो विधायक वालसिंह मैडा से चर्चा कर क्षेत्र के किसानो से मुलाकात कर समस्या जानने की कोशिश करेंगे और उचित मुआवजे की मांग सरकार से करेगे।

खेत मे खड़ी फसल पर कम्पनी ने चला दिए अपने भारी वाहन।

इस तरह बिछाई जा रही है पाइप लाइन।

अपने बंगलों के आगे की सुरक्षा हटाईये और स्कूलों के आगे लगाईये

अंधगति से दौड़ती बसों पर भी नहीं है कोई नियंत्रण, आरटीओ मेडम गरीबों पर करती है कार्रवाई

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मील मंसूरी

सोमवार को शहर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हृदय विदारक घटना ने सबको हिलाकर कर रख दिया। ग्राम मींडल में एक स्कूली छात्र को सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार बस ने बड़ी बेरहमी से रौंद डाला। बालक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्राम गोपालपुरा का एक 9 वर्षिय छात्र रितेश सोमवार को घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। मगर स्कूल के सामने ही तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद भी तेज रफ्तार बस को चालक ने नहीं रोका। घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर बस रोकी और चालक फरार हो गया। घटना के बाद परीजन मृतक रितेश का शव सड़क किनारे रखकर विलाप करते रहे, डेढ़ घंटे तक यहां कोई जिम्मदार नहीं पहुंचा। घटना के बाद किसी जिम्मेदार के नही पहुंचने से ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होने चक्का जाम कर दिया। करीब डेढ़ घंटे बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाईश देकर रास्ता खुलवाया। जिसके बाद शव को पीएम के लिए भेजा गया।

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों से जब चर्चा की तो उन्होने बताया कि, यह कोई पहला हादसा नही है। इससे पहले भी यहां कई घटनाएं हो चुकी है और कई लोग अपनी जान गवा चुके है। ग्रामीणों से घटना होने का कारण जानना चाहा तो वे बताते है कि, जब से यह रोड बना है तब से इस पर वाहनों की रफ्तार बहुत अधिक हो गई है। मार्ग पर किसी तरह के कोई संकेतक भी ठेकेदार द्वारा नहीं लगाए गए है और न ही किसी तरह का कोई गति अवरोधक बनाया गया है। बस यही कारण है कि यहां पिछले एक साल से दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। जबकि गांव के सरपंच द्वारा कई बार इस मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं से अवगत कराते हुए गति अवरोधक बनवाने की मांग प्रशासन से की गई। मगर अंधा, गूंगा व बहरा प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पाया। जब भी दुर्घटना होती है, किसी की जान जाती है तो पुलिस अपना काम निकालने के लिए आश्वासनों का पुलिंदा ग्रामीणों को थमा देती है। मगर बाद में स्थिति वही ÷ढाक के तीन पात÷ सी हो जाती है। मिंडल की जिस स्कूल के सामने यह दुर्घटना घटी उसका मेन गेट लगभग सड़क से सटा हुआ है और यहां पर किसी तरह का कोई संकेतक भी नहीं है ना ही कोई गति अवरोधक बना हुआ है। इस स्कूल में पढने वाले बच्चों की संख्या भी अच्छी-खासी है। दुर्घटना का हमेशा भय भी बना रहता है। मगर प्रशानिक लचर व्यवस्था के चलते इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है।

विडम्बना यह कि देवझिरी से करड़ावद बड़ी तक बने इस मार्ग के बीच ही शहर की उत्कृष्ट सड़क बनी हुई है। इसी उत्कृष्ट सड़क पर जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यायल व निवास है। अब विडम्बना यह कि कलेक्टर कार्यालय से लगाकर कलेक्टर बंगले तक कुछ ही मिटर की दूरी में करीब चार जगहों पर गति अवरोधक बने हुए है। बावजूद इसके कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक बंगलों के आसपास अत्यधिक सुरक्षा के मद्देनजर यातायात के अस्थाई बेरीकेट भी लगे हुए है। अब सवाल यह उठता है कि, अधिकारियों के बंगलों के बाहर से होकर गुजरने वाली सड़क पर यातायात को कंट्रोल करने के इतने इंजातम क्यों व किस लिए..? जबकि इसके विपरीत इस सड़क के किनारे बने स्कूल, कालोजों और अन्य संस्थाओं के आसपास संकेतक व गति अवरोधक तक नहीं। प्रशासन को चाहिए कि आम और खास की खाई को पाटते हुए इस मार्ग पर पडने वाली शैक्षणिक संस्थाओं, महाविद्यालयों व अन्य संस्थाओं के आसपास भी वैसी ही सुरक्षा मुहैया कराए जैसी कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने अपने बंगलों के आसपास करवाई है।

सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जिले में बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर जिला परिवहन अधिकारी का भी कोई नियंत्रण नहीं है। जिलें में अवैध बस संचालकों की भी बाढ़ सी आई हुई है। कई बसें बिना परमीट के दौड़ रही है तो कईयों के पास गाड़ीयों के पूरे कागजात भी नहीं है। झाबुआ बस स्टेंड से चलने वाली यह बसें सवारियों के परिवहन को लेकर इतनी लापरवाह है कि सवारियां बैठाने को लेकर या वाहन में बैठी सवारियां की जान दाव पर लगा देते या रास्ते चलते लोगों की जान के दुश्मन बन जाते। सवारियों को बैठाने की प्रतिस्पर्धा में यह लोग यह भूल जाते है कि, इंसान की जान की कीमत क्या है। इसी का परिणाम सोमवार को ग्राम मिंडल में दुर्घटना का शिकार हुए रितेश को अपनी जान गवा कर भुगतना पड़ा। जिस गुर्जर बस से यह दुर्घटना हुई उस बस के चालक ने मानों गाड़ी को रोकने तक का प्रयास ही न किया हो या फिर उस बस में ब्रेक ही नहीं लगे। चाहे जो भी हो लेकिन सवाल तो आरटीओ मेडम कृतिका मोहटा की कार्यप्रणाली पर उठेंगे। आखिर इस तरह की बसों का संचालन जिले में हो ही क्यों रहा है।

ग्राम करड़ावद में नेशनल हाइवे के किनारे गुर्जर ढाबे पर इसके प्रयत्क्ष प्रमाण देखने को मिल रहे है। जहां से दिनभर में कई स्लिपर कोच बसें मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह भरकर अन्य राज्यों में परिवहन कर रही है। कहने को तो यह प्रत्यक्ष रूप से टूरिस्ट बसें है, लेकिन पूरी तरह से सवारियों पर चल रही है। जिले के आदिवासी ग्रामीण जो रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर जाते है उन्हे इन टूरिस्ट बसों में मनमाना किराया लेकर भेड़-बकरियों की तरह भरकर ले जाया जाता है यह बात किसी से छुपी नहीं है। मगर जिला परिवहन अधिकारी मेडम कृतिका मोहटा की आंखों पर न जाने कितने नंबर का चश्मा लगा हुआ है जो उन्हे इस तरह का परिवहन करती बसें दिखाई नहीं देती। या यूं कहें कि इन अवैध बस संचालकों ने मेडम की आंखों पर गांधी छाप पट्टी बांध दी है। क्योंकि लक्ष्य की पुर्ति और अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए तो मेडम को गरीबों की रोजी -रोटी ही दिखाई देती है। जिसका प्रमाण मेडम ने खुद पिछले दिनों 22 व 25 नवंबर को गरीब ऑटो चालकों पर कार्रवाई कर ऑटो रिक्शा जप्त करते हुए दिया है। वैसे भी माही की गूंज तो अपने पिछले अंक में ही लिख चुका है कि ''गरीबों के गले नख देने से क्या फायदा मेडम मोहटा, मगरमच्छों को छोड़ मछलियों का शिकार यह तो बहुत नाइंसाफी है''। हालांकि आरटीओ मेडम ने सोमवार को हुई इस हृदय विदारक घटना के बाद सोमवार रात को ही झाबुआ में तो नही मगर राणापुर में जरूर कार्रवाई करते हुए दो बसों को जप्त किया। अन्य बसों की चेकिंग भी की गई। मगर आरटीओ द्वारा की गई यह कार्रवाई ÷ऊंट के मुंह में जीरा÷ ही साबित होगी। क्योंकि इन अवैध बस संचालकों का मायाजाल पूरे जिले में फैला हुआ है। लगभग जिले के हर कस्बे से हर रोज इस तरह की बसें सवारियों ढो रही है। अधिकतर स्लीपर बसें है जो मजदूरों को जिले से अन्य राज्यों में लेकर जाती है। इन वाहनों में नियमानुसार शायद ही कोई सुविधा उपलब्ध रहती। देखने में एक दम से कंडल व अटाला बसों में मनमाना किराया वसूलते हुए ग्रामीणों को ठूंस-ठूंस कर भरा जाता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422